प्रकाशन का 44 वां वर्ष

शैल समाचार

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक

ई-पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 44 अंक-8 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 18-25 फरवरी 2019 मूल्य पांच रूपए

उद्योगों को आमन्त्रण के साथ ही उनकी लूट पर भी नज़र रखनी होगी

शिमला/शैल। जयराम सरकार प्रदेश की आर्थिक सेहत को सुधारने तथा बढ़ती बेरोजगारी पर लगाम लगाने के लिये राज्य में नये उद्योग स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। क्योंकि सरकार की नजर में उद्योग ही एक ऐसा अदारा है जिनके माध्यम से निवेश आने पर जीडीपी सुधरेगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इस

नीति पर काम करते हुए सरकार ने शिमला में आयोजित इन्वैस्टर मीट में उद्योगों के साथ 18 हजार करोड़ से अधिक के निवेश के उद्योपतियों के साथ एमओयू साईन किये हैं इस 18 हजार करोड़ के संभावित निवेश में से कितना सही में जमीनी हकीकत बन पायेगा यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। क्योंकि पूर्व में धूमल और वीरभद्र शासन में भी ऐसे प्रयास और प्रयोग हो चुके हैं लेकिन उनमें कितनी सफलता हासिल हुई है और कितना निवेश प्रदेश को मिल पाया है इसके सही आंकड़े संवद्ध प्रशासन नही दे पाया है। माना जाता है कि शीर्ष प्रशासन इस तरह की योजनाएं जीडीपी के आंकड़े सुधारने के लिये लाता है ताकि कर्ज लेने की सीमा बनी रही।

इस समय प्रदश में कितने उद्योग कार्यरत है और उनमें कितना निवेश है तथा कितने लोग काम कर रहे है इसको लेकर उद्योग विभाग ने 2017 में एक प्रपत्र तैयार किया था। इसके मुताबिक प्रदेश में 40 हजार उद्योग पंजीकृत हैं जिनमें 17 हजार करोड़ का निवेश है तथा इन उद्योगों में 2,58,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। इस बार सदन में आये एक प्रश्न के उत्तर में उद्योगों की संख्या 49 हजार बतायी गयी है लेकिन इनमें कितना निवेश है और कितने कर्मचारी हैं इस पर कुछ नही कहा गया है। इसी बीच आयी एक कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि हिमाचल के 2009 से 2014 के बीच विभिन्न करों में 35 हजार करोड़ की राहत मिल चुकी है। लेकिन इसके बावजूद यह उद्योग प्रदेश के युवाओं को वांच्छित रोजगार नही दे पाये हैं। 35 हजार करोड़ का यह आंकड़ा सरकारी फाईलों में दर्ज रिटर्नज पर आधारित है। यह दावा है केन्द्र के वित्त विभाग का जिसे प्रदेश की अफसरशाही मानने को तैयार नही हैं लेकिन कैग में दर्ज इस रिपोर्ट को प्रदेश के बड़े बाबू खारिज भी नही कर पाये हैं। कैग रिपोर्ट में दर्ज आंकड़ो और प्रदेश के उद्योग विभाग के 2017 के प्रपत्र के अनुसार इन उद्योगों के माध्यम से 52 हजार करोड़ निवेश से केवल तीन लाख लोगों को ही रोजगार मिल पाया है कि क्या प्रदेश की उद्योग नीति सही दिशा में है या नही।

आज उद्योगों को आमन्त्रि करने के लिये उन्हे कई तरह के प्रोत्साहन दिये जाते हैं। सबसे बड़ा तो यह है कि यह उद्योगपत्ति प्रदेश के बैंको से ही कर्ज लेकर निवेश करते हैं। जब यह कर्ज लौटाया नही जाता है तब एनपीए हो जाता है। आज प्रदेश के सारे सहकारी बैंक तक एनपीए में है। प्रदेश की वित्त निगम इन्ही उद्योगों के कारण डूब चुका है लेकिन प्रदेश की शीर्ष अफसरशाही और राजनीतिक नेतृत्व इस गंभीर पक्ष की ओर एकदम आंखे बन्द करके बैठा है। बल्कि कई जगह तो केन्द्र की योजनाओं के नाम पर कुछ शातिर लोग बैंक प्रबन्धन से मिलकर लोगों को लूट रहे हैं और संवद्ध प्रशासन इस बारे में आंख कान बन्द करके बैठा हुआ है। यहां तक की पुलिस भी ऐसी शिकायतों पर इन लोगों के प्रभाव में आकर कोई कारवाई नही कर रही है। इसलिये आज यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि उद्योगों को आमन्त्रित करने के साथ ही उनकी लूट पर भी नजर रखनी होगी।

केन्द्र सरकार की स्मॉल, माईक्रो और मीडियम उद्योगों को प्रोत्साहन एवम् संरक्षण देने की योजना है। यह योजना

CGTMSE योजना के नाम पर बैंक की मिलीभगत से हो रहा फ्रॉड शिकायत मिलने के बावजूद पुलिस नही कर रही मामला दर्ज

2006 में अधिसूचित हुई थी। इसके तहत उद्योग लगाने वाले व्यक्ति को दो करोड़ ऋण लेने के लिये किसी भी तरह की धरोहर/संपत्ति को बैंक में गिरवी रखने की आवश्यकता नही थी क्योंकि इसके लिये सरकार ने एक CGTMSE(Credit Guarntee Fund trust for Micro and small Entetprises) स्थापित कर रखा था। इस योजना के तहत स्थापित यदि कोई इकाई डिफाल्टर हो जाती है तो यह ट्रस्ट ऋण देने वाले बैंक को उसकी 50/75/80/85 प्रतिशत तक भरपाई करता है। इस योजना में 7-1-2009 को संशोधन करके ट्रस्ट की जिम्मेदारी 62.50% से 65% तक कर दी गयी थी। इसके बाद 16-12-2013 को इसमें फिर संशोधन हुआ और ट्रस्ट की जिम्मेदारी 50% तक कर दी गयी। इस योजना के तहत स्थापित हो रही इकाई और उसको स्थापित करने वाले का आकलन करना और उससे पूरी तरह आश्वस्त होना यह जिम्मेदारी ऋण देने वाले बैंक प्रबन्धन की थी। अभी पिछले दिनों मोदी सरकार ने भी इसी योजना के तहत 59 मिनट में एक करोड़ का ऋण देने की घोषणा की है। यह इसी आधार पर संभव है कि ऋण लेने वाले को कुछ भी धरोहर के रूप में बैंक के पास गिरवी नही रखना है केवल बैंक प्रबन्धन को ऋण लेने वाले और उसकी योजना से आश्वस्त होना है। केन्द्र सरकार की यह एक बहुत बड़ी योजना है और इसके लिये एक पूरा मन्त्रालय स्थापित है। वीरभद्र सिंह भी इसके केन्द्र में मन्त्री रह चुके हैं। इस योजना की पूरी जानकारी आम आदमी से ज्यादा बैंको के पास है और एक तरह से उन्हें ही लोगों को इसके लिये प्रोत्साहित करना है।

जब सरकार उद्योग स्थापित करने के लिये इस तरह की सहायता का आश्वासन देगी तो यह स्वभाविक है कि कोई भी आदमी इसका लाभ उठाना चाहेगा। इसी का फायदा उठाकर मोहम्मद शाहिद हुसैन ने पांच अलग नामों से उद्योग इकाईयां स्थापित की। शाहिद हुसैन हिमाचल का निवासी नही था और यहां पर उसके पास कोई संपत्ति नही थी। इसलिये उसे यहां पर उद्योग लगाने के लिये स्थानीय लोगों की हिस्सेदारी चाहिये थी। इस हिस्सेदारी को हासिल करने के लिये उसने स्थानीय लोगों से मित्रता बनानी आरम्भ कर दी और सबको अपना परिचय एक मुस्लिम बुद्धिजीवि शायर के रूप में दिया। उसकी शायरी से प्रभावित होकर कुछ लोग उसके प्रभाव में आ गये। प्रभाव में आने के बाद उसने इन लोगों को केन्द्र की इस उद्योग योजना की जानकारी देना शुरू किया। इसका विश्वास दिलाने के लिये केनरा बैंक के प्रबन्धक एस के भान से मिलाना शुरू किया। बैंक मैनेजर ने भी लोगों को इस योजना की जानकरी दी और बताया कि इसमें उन्हे ऋण लेने के लिये कुछ भी गिरवी रखने की आवश्यकता नही है। स्वभाविक है कि जब ऋण देने वाला बैंक भी ऐसी योजना की पुष्टि करेगा तब आदमी उद्योग लगाने के लिये तैयार हो ही जायेगा। उद्योग इकाईयां स्थापित कर ली यह इकाईयां आर आर वी क्रियेशनज़, रामगढ़िया इन्टरप्राईज़िज, बाला जी इन्टर प्राईज़िज, आर के इन्डस्ट्रीज और पारस होम एप्लांईसेज़ शाहिद के षडयन्त्र का असली चेहरा पासर होम एप्लॉईसैज मे सामने आया। यहां पर उसने पीयूष शर्मा को अपना हिस्सेदार बनाया। पीयूष के पिता कुलदीप शर्मा का यहां एक होटल और अपना बड़ा मकान है। शाहिद की नज़र इस संपत्ति पर आ गयी। उसने पीयूष को पार्टनर बनाकर जून 2013 में केनरा बैंक से ऋण स्वीकृत करवा लिया। फिर नवम्बर 2013 में पीयूष के पिता कुलदीन शर्मा को यह कहानी गढ़ी कि उसे 1.10 लाख यू एस डॉलर का आर्डर मिला है और इस आर्डर को पूरा करने के लिये उसे एक करोड़ के अतिरिक्त ऋण की आवश्यकता है यदि कुलदीप शर्मा इस ऋण के लिये अपना मकान कुछ समय के लिये बैंक में गिरवी रखने को तैयार हो जायें तो यह आसान हो जायेगा। बेटे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वह इसके लिये तैयार हो गये। शाहिद उन्हें केनरा बैंक ले गया वहां बैंक प्रबन्धक ने भी इसकी पुष्टि कर दी और कुलदीप को मकान मारटगेज करने के लिये राजी कर लिया। 9.12.2013 को यह मारटगेज डीड साईन हो गयी। यह डीड साईन होने के बाद अन्य इकाईयों की जानकारी सामने आयी और कुलदीप के बेटे ने शाहिद के साथ अपनी पार्टनरशिप भंग कर दी। कुलदीप शर्मा ने बैंक को यह मारटगेज डीड रद्द करने के लिये लिखित में दे दिया क्योंकि इस डीड के एवज में बैंक ने कोई अतिरिक्त ऋण जारी नहीं किया था। बैंक के साथ ही कुलदीप ने संबन्धित तहसीलदार को भी सूचित कर दिया कि यह इस डीड पर अमल न करे। लेकिन तहसीलदार ने कुलदीप के आग्रह को नजरअन्दाज करके मकान बैंक के नाम लगा दिया। इस सारे किस्से की पुलिस को भी लिखित में शिकायत दे दी गयी लेकिन पुलिस ने आज तक शाहिद और बैंक प्रबन्धन के खिलाफ कोई मामला दर्ज नही किया है।

कुलदीप जैसा ही व्यवहार अन्य तीन लोगों के साथ भी हुआ है वह भी पुलिस को शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई कारवाई सामने नही आयी है। अब यह भी सामने आया है कि आर के इन्डस्ट्रीज़ शाहिद की पत्नी के नाम है लेकिन यह इकाई केवल कागजों में ही कही जा रही है और इसी केनरा बैंक प्रबन्धन ने इस ईकाई के नाम पर भी कोई 50 लाख का ऋण दे रखा है। इन सारे उद्योगों को इसी बैंक से करीब दो करोड़ का ऋण दिया जा चुका है और इन उद्योगों में हिस्सेदार बनाये गये सारे स्थानीय लोग इस षडयन्त्र का शिकार हो चुके हैं। यह सारे ऋण एक ही बैंक प्रबन्धक द्वारा दिये जाना यह प्रमाणित करता है कि यह एक सुनियोजित षडयन्त्र है जिसमें बैंक प्रबन्धक की सक्रिय भूमिका रही है। अब जब पुलिस शिकायत मिलने के बाद भी मामला दर्ज नही कर रही है तब पुलिस की भूमिका भी सन्देह के घेरे में आ गयी है। इस षडयन्त्र का शिकार हुए लोगों की हताशा कब क्या गुल खिला दे इसका अनुमान लगाना कठिन है।

CGTMSE -Credit Guarantee Fund trust for Miicro and Small Enterprises:A special protection is given to the micro, small and Medium enterprises via the MSME Act, 2006. These are small scale industries which require immunity and special protection to flourish. These industries from the very backbone of our Indian Economy.One of the government-sponsored schemes for MSMEs is the CGTMSE (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and small Enterprises).

What is the CGTMSE?

The whole idea behind this trust is **to provide financial assistance to these industries without any third party guarantee/ or collateral.** These schemes provide the assurance to the lenders that in case of default by them a guarantee cover will be provided by trust in the ration of 50/75/80/85 percent of the amount so given.

भविष्य की पीढ़ियों के लिए पानी और उपजाऊ भूमि बचाओ: आचार्य देवव्रत

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती को अपनाने पर बल देते हुए कहा कि जल, वायु और खाद्यानों में रसायनों का अत्यधिक उपयोग गम्भीर समस्या बन गया है।

राज्यपाल आचार्य देवव्रत दीनबंधु फाउंडेशन द्वारा 14 फरवरी, 2019 को जम्मू-कश्मीर में पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित एक समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरा देश एक जुट हो कर उन लोगों को जवाब दे रहा है, जो भारत की एकता और अखण्डता के लिए घातक है।

उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार पंजाब तथा हरियाणा में जल स्तर हर वर्ष चार फुट तक कम हो रहा है और अगर स्थिति यही रही तो कुछ वर्षों में आने वाली पीढ़ियों के लिए बंजर एवं जलविहीन भूमि ही रह जाएगी। उन्होंने कहा कि इसका एक मात्र समाधान प्राकृतिक खेती है जिसके द्वारा भू-जल स्तर को पुनर्जीवित किया जा सकता है और हमें जैविक व स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद प्राप्त होंगे।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहले ही प्राकृतिक खेती को अपना लिया है तथा किसानों को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले वर्ष में तीन हजार से अधिक किसानों ने इस प्रणाली को अपना लिया है और इस वर्ष के लिए 50 हजार किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में 40 लाख से अधिक किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपना लिया है।

उन्होंने युवाओं को नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि युवा राष्ट्र की भविष्य है और देश के विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं परन्तु यह चिंता का विषय है कि वे नशे के शिकार हो रहे है।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि लोगों को एक समृद्ध, विकसित और शान्तिपूर्ण समाज के निर्माण के लिए एकजुट होकर सामाजिक बुराइयों के विरूद्ध लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि बच्चों में नैतिक मूल्यों और जिम्मेदारी की भावना जागृत करने में शिक्षकों और अभिभावकों की शुरू से ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिससे उन्हें सामाजिक बुराइयों से बचाया जा सके।

सफीदों विधानसभा क्षेत्र के विधायक जस्वीर देशवाल और दीनबंधु फाउंडेशन के अध्यक्ष सुरेन्द्र ढल भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

इससे पूर्व, राज्यपाल ने मिनर्वा पब्लिक स्कूल कैलराम के परिसर में नशामुक्ति और प्राकृतिक खेती पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को अपनी मानसिकता बदल कर अपनी बेटियों को बेहतर शिक्षा के समान अवसर देने का आग्रह किया ताकि वे राष्ट्र की प्रगति व विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। उन्होंने कहा कि आज लड़कियां सभी क्षेत्रों में लड़कों से बेहतर प्रदर्शन कर देश को गौरवान्वित कर रही है।

भारत को आध्यात्मिक एवं भौतिक रूप से श्रेष्ठ बनाने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण-सैजल

शिमला/शैल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सहकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि भारत को आध्यात्मिक एवं भौतिक रूप से श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं को एक निष्ठ होकर कार्य करना होगा। डॉ. सैजल सोलन जिला के नालागढ़ उपमंडल के बद्दी के बद्दी विश्वविद्यालय में अंतरराज्यीय विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता 'लक्ष्य' के शुभारंभ के उपरांत उपस्थित छात्रों, अध्यापकों एवं अन्य को संबोधित कर रहे थे।

इस खेल प्रतियोगिता में 8 विश्वविद्यालयों के लगभग 150 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। दो दिवसीय इस प्रतियोगिता में बॉस्केटबॉल, वॉलीबाल, टेबल टेनिस तथा फुटबाल के मुकाबले होंगे। प्रतियोगिता में बद्दी विश्वविद्यालय, चितकारा विश्वविद्यालय बद्दी, चितकारा विश्वविद्यालय राजपुरा, पंजाब, इटरनल विश्वविद्यालय बड़ू साहिब सिरमौर, शूलिनी विश्वविद्यालय सोलन, एपीजी विश्वविद्यालय शिमला, बहारा विश्वविद्यालय, वाकनाघाट, सोलन तथा शिवा महाविद्यालय बिलासपुर भाग ले रहे हैं। डॉ. सैजल ने कहा कि भारत को प्राचीन समय से ही आध्यात्मिक एवं शिक्षण कार्यो में अपनी स्थापित पद्धति एवं कार्य के लिए जाना जाता है। आज भारत विकास के अनेक मानकों पर विश्व को राह दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विश्व का श्रेष्ठतम देश बनाने के लिए कृतसंकल्प हैं। यह कार्य युवाओं की सक्रिय भूमिका के साथ ही संपन्न होगा। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी असीमित ऊर्जा को देशहित में लगाएं। सहकारिता मंत्री ने कहा कि भारत एक युवा देश है और केन्द्र एवं प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि प्रत्येक क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी हो।

डॉ. सैजल ने कहा कि खेल प्रतियोगिताएं युवाओं के सर्वांगीण विकास में सहायक होती हैं। उन्होंने कहा कि सभी छात्रों को रूचि अनुसार खेलों में भाग लेना चाहिए। इस दिशा में प्रदेश सरकार निरंतर प्रयायसरत है। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा निर्माण योजना के तहत राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से दो बड़े बहुद्देशीय खेल मैदान निर्मित करने का निर्णय लिया है। इन खेल मैदानों में युवाओं को जिम की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार इसके लिए 15 लाख रुपये प्रदान करेगी। 15 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि विभिन्न अन्य योजनाओं इत्यादि से सुनिश्चित बनाई जाएगी।

साइवर अपराध थाना शिमला द्वारा धारक को फोन में डेस्क एप्प डॉउनलोड न करने के निर्देश

शिमला/शैल। राज्य साईवर अपराध थाना शिमला निरंतर साइवर अपराधिंयो द्वारा किए जा रहे अपराधों से निपटने के लिए कृत संकल्प है। साइवर अपराधी हर रोज नई तकनीक का उपयोग करके आम जनमानस को ठगने में सक्रिय रहते है। वर्तमान समय में पाया जा रहा है कि साइवर अपराधी अपने टारगेट (पीडित) व्यक्ति को विश्वास में लेकर अपने फोन में गुगल पलेस्टोर से Any Desk App या Team Viewer App Download व अन्य Applications को download करने का निर्देश(आग्रह) करता है। जब यह App Download हो जाता है तो कुछ अंको का एक कोड जनरेट होता है। उसे साइवर अपराधी Share करने को कहता है। जब यह कोड अपराधी अपने मोबाईल में फीड़ करता है तो उससे धारक (पीडित) व्यक्ति के मोबाईल फोन या कम्पयूटर का रिमोट कन्ट्रोल अपराधी के पास चला जाता है तथा उसको Access की अनूमती धारक से ले लेता है। अनूमती मिलने के पश्चात अपराधी धारक के फोन या कम्पयूटर का सभी डाटा चूरा लेता है एवम इसके माध्यम से Unified Payment Interface (UPI) द्वारा फोड ट्राजेक्शन करने में सफल हो जाता है। इसके द्वारा धारक फोन में Install अन्य Payment App या Paytm के द्वारा भी फोड ट्रांजेक्शन करने में सफल हो जाता है। देश के कई भागों में इस Any Desk app के द्वारा भारी ट्रांजेक्शन की शिकायत आ रही है। इस संद्धर्भ में राज्य साइवर अपराध थाना शिमला द्वारा फेसबुक, ट्वीटर के माध्यम से आम जनता को सचेत रहने के निर्देश दिए गए है कि Any Desk App भूल कर भी Download न करें और न ही इसका access अन्य अनजान व्यक्तित को दें।

NOTICE INVITING TENDER
HP.PWD KANGRA

Sealed item rate tenders on form 6 & 8 are invited by the **Executive Engineer, Kangra Division, HP: PWD,** Kangra on behalf of the Governor of Himachal Pradesh from the approved and eligible contractors/firms enlisted in **HPPWD** in the appropriate class for the work mentioned below on **14-03-2019 up to 10-45 A.M.** and will be opened on the same day at **11:00 A.M.** in the presence of intending contractors or their authorized representatives. The tender forms can be obtained from his office on cash payment (non refundable) on any working day from **11-03-2019 to 13-03-2019.** The applications for the issue of tender forms will be received latest by **08-03-2019 up to 12.00 Noon.** The applications for issue of tender forms accompanied with enlistment letter/or renewal letter and the earnest money in the shape of National Saving Certificates/Saving Account/Time deposit Account in any of the Post Office in Himachal Pradesh duly pledged in favour of **Executive Engineer, Kangra Division, HPPWD, Kangra.**

The conditional tenders and the tenders received without earnest money will summarily be rejected. The offer of the tender shall be kept open for **120 days.**

Work No.1:- A/R & M/O Kangra to Matour road (SH:-P/L Bituminous Macadam & Bituminous concrete pavement km. 3/00 to 3/700) Estimated cost: Rs. 4,96,848/- Earnest Money: Rs. 9,950/- Time Limit One Month Cost of tender 350/-.

Work No.2:- A/R & M/O Kangra to Matour road (SH:-P/L Bituminous Macadam & Bituminous concrete pavement km. 3/700 to 4/250) Estimated cost: Rs. 4,97,509/- Earnest Money: Rs. 9,950/- Time Limit One Month Cost of tender 350/-.

Work No.3:- A/R & M/O Kangra to Matour road (SH:-P/L Bituminous Macadam & Bituminous concrete pavement km. 4/250 to 5/00) Estimated cost: Rs. 4,97,115/- Earnest Money: Rs. 9,950/- Time Limit One Month Cost of tender 350/-.

Work No.4:- A/R & M/O Chambi D/Shala road (SH:-P/L Bituminous concrete pavement at various RDs) Estimated cost: Rs. 4,98,851/- Earnest Money: Rs. 10,000/- Time Limit One Month Cost of tender 350/-

TERMS & CONDITIONS:-

1. The contractors/firms should be registered as or/dealer under HP Sales Tax Act.1968.
2. The intending contractors/firms shall have to produce the copy of latest enlistment and renewal enlisted in HPPWD.
3. The contractors is required to submit an affidavit for not having more than two works in hand in the shape of affidavit duly attested by the competent authority.
4. If any of the date mentioned above happened to be Gazetted Holiday the same shall be processed on next working day.
5. The contractor should quoted the rates of all the items in the tender both in figures and in words failing which tender is likely to be rejected.
6. The copy of Employees Provident Funds (EPF Number) should be attached with the application.
7. Minimum one similar work done of amount not less than 40% (forty percent) of the estimated cost (without Liquidated Damage or compensation) in last five years).
8. The Earnest Money for the above works should be required at the time of sale of tender forms.
9. All the required document should be submitted with the application otherwise single application may be rejected.
10. The Executive Engineer reserves the right to accept/reject any tender/ application or all tenders without assigning any reason.
11. The Contractor should be sole proprietorship of Hot Mix Plant and other required machinery with proof of ownership i.e. RC etc. No affidavit / undertaking to tie up will be entertained.

Adv. No.-4822/18-19 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक-जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार-ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTICE INVITING TENDER

Sealed item rate tender on Form No. 6&8 are invited on behalf of Governor of Himachal Pradesh by the **Executive Engineer, Electrical Division, HPPWD, Mandi (H.P.)** for the following works from the approved and eligible contractors enlisted in HPPWD (Electrical) department so as to reach in his office on or before **18.03.2019 up-to 10.30 A.M.** and will be opened on the same day at **11:00 A.M.** in the presence of intending contractors or their authorized representatives. The application for issuing of tender form will be received in his office against cash payment Rs. 350/-(Non-refundable) for each work on or before **16.03.2019 up to 01:00 P.M.** and the tender forms can be had from his office on same day. The application for the purchase of tender documents should be accompanied with earnest money of each work separately in the shape of National Saving Certificate/FDR/ Call Deposit / Saving Bank account / Bank draft of any Schedule Bank / Post Office duly pledged in favour of the **Executive Engineer, Electrical Division, HP.PWD, Mandi (H.P.).** Conditional tenders and the tenders received without earnest money will be rejected. The receipt of application for issue of tender forms by post shall not be entertained / considered in any case. The tender forms shall be issued to registered Contractors or their authorized representatives. The copy of enlistment / renewal order and valid Electrical License shall be attached with the application for purchase the tender document. The ambiguous / telegraphic / conditional / fax / E-mail or by post tenders shall also not be entertained / considered in any case. The tender shall be issued to those Contractors / Firms who are found eligible, suitable and competent. The decision of the Executive Engineer regarding suitability / eligibility / competency of Contractors/ Firms shall be final binding on the Contractors / Firms applying for the issuing of the tender. The offer for the tenders shall be kept open for 120 days. The Executive Engineer reserves the right to reject the tender without assigning any reasons, if there happens to be any holiday the same will be opened on next working day.

Work No. 1:- C/o Additional Accommodation on the existing Building at Rest House Chattri, District Mandi HP **Estimated Cost: -** Rs. 362394/-only, **Earnest money: -** Rs. 7250/- only, **Time allowed:** Along with civil work.

Work No. 2:- C/o Additional Accommodation for Government High School at Kotgarh, District Mandi HP **Estimated Cost: -** Rs. 177768/-only, **Earnest money:** - Rs. 3600/- only, **Time allowed:** Along with civil work

Work No. 3:- C/o Assistant District Attorney Building, Bassa at Gohar, Tehsil- Chachiot, District Mandi HP **Estimated Cost: -** Rs. 160284/-only, **Earnest money: -** Rs. 3250/- only, **Time allowed:** Along with civil work

Work No. 4:- C/o Multipurpose Building at Malana, District Kullu HP (SH: Providing EI therein) Balance Work **Estimated Cost:** Rs. 120531/-only, **Earnest money: -** Rs. 2450/- only, **Time allowed:** Along with civil work

Work No. 5:- C/o Additional Accommodation for Government Senior Secondary School at Dhar, Tehsil- Padhar, District Mandi HP **Estimated Cost:** - Rs. 109729/-only, **Earnest money: -** Rs. 2200/- only, **Time allowed:** Along with civil work

Adv. No.-4950/18-19 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

केन्द्रीय मंत्री ने किए 4500 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय राजमार्गों के शिलान्यास

शिमला/शैल। सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प के केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की उपस्थिति में कांगड़ा जिले

के गग्गल में 4459.24 करोड़ रुपये की विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया।

नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग-154 के तहत 1572.90 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले पंजाब-हिमाचल सीमा से सिहुणी खण्ड के 37.05 किलोमीटर के फोर लेनिंग कार्य का शिलान्यास किया।

केन्द्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग 707 के तहत 1356 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले 104.60 किलोमीटर के पांवटा साहिब-गुम्मा-फेडुजपुल खण्ड के कार्य की आधारशिला भी रखी। ।

नितिन ने राष्ट्रीय राजमार्ग 70 के तहत 1,334 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले हमीरपुर-मंडी खण्ड के 109.75 किलोमीटर के कार्य तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 503 के तहत 51.09 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले 15.75 किलोमीटर के ऊना-भीरू खण्ड के कार्य का शिलान्यास किया।

उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 503 के तहत 46.13 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले 23.10 किलोमीटर के मटौर-धर्मशाला -मैकलोडगंज खण्ड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के तहत 30 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले सात किलोमीटर के पांवटा साहिब टाऊन खण्ड का शिलान्यास किया।

केन्द्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग 305 के तहत 29.07 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले 94 किलोमीटर के सैंज-लुहरी-आनी-जलोड़ी-बंजार-ऑट खण्ड के बीच रिटेनिंग वॉल और क्रैश बैरियर के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया।

इसके अतिरिक्त उन्होंने 40.05 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाली 49 किलोमीटर की बारोह चौक-देहरीयां-जंदराह-टाली-लगरू-डोला खुडिंया-नाहलियां सड़क का भी शिलान्यास किया।

नितिन गडकरी ने कहा कि ये सभी सड़कें बेहतर तथा सुरक्षित यातायात सुविधा प्रदान करने के अलावा इन क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों को भी सुविधा प्रदान करने में सहायक होंगी। इससे युवाओं को रोज़गार सृजन सुनिश्चित करने के अतिरिक्त इस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी।

पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद शांता कुमार, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर, शहरी विकास मंत्री सरवीन चौधरी, कृषि मंत्री डॉ. राम लाल मारकंडा, स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार, राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला, सीजीएम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मुनीष रस्तोगी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुख्य अभियन्ता बी.के. सिन्हा भी इस अवसर पर अन्य लोगों के साथ उपस्थित थे।

हिमाचल प्रदेश के 11 जिलों में वानरों को किया पीड़क जन्तु (वर्मिन) घोषित

शिमला/शैल। वन मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने जानकारी दी कि प्रदेश के 11 जिलों की 91 तहसीलों एवं उप-तहसीलों में वानरों को एक वर्ष की अवधि के लिए पीड़क जन्तु (वर्मिन) घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यह मामला बार-बार केन्द्र सरकार के समक्ष रखा और कहा कि हिमाचल प्रदेश में वानरों के कारण मनुष्य एवं फसलों को क्षति पहुँच रही है तथा इस समस्या के निपटारे के लिए वानरों को पीड़क जन्तु घोषित करना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि इस सन्दर्भ में केन्द्रीय सरकार ने 14 फरवरी, 2019 को अधिसूचना जारी कर वानरों को 91 तहसीलों एवं उप-तहसीलों में पीड़क जन्तु घोषित कर दिया है, जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र में 21 फरवरी, 2019 को किया गया। यह अधिसूचना एक वर्ष की अवधि तक लागू रहेगी।

उल्लेखनीय है कि 24 मई, 2016 को वानरों को हिमाचल के दस जिलों की 38 तहसीलों एवं उप-तहसीलों मे पीड़क जन्तु घोषित किया गया था, जिसकी अवधि को 20 दिसम्बर, 2017 में एक वर्ष के लिए बढ़ाई गई थी।

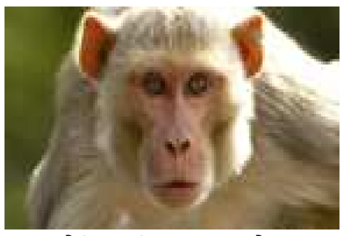

गोबिन्द सिहं ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में वन क्षेत्रों के बाहर वानरों द्वारा मनुष्यों एवं खेती को हानि पहुंचाने के मामले सामने आ रहे थे इसलिए इस समस्या को प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार के समक्ष रखा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों के फलस्वरूप 91 तहसीलों एवं उप-तहसीलों में वानरों को पीड़क जन्तु घोषित करवाने में सफलता हासिल हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे सभी प्रदेशवासियों विशेषकर किसानों एवं बागवानों को राहत मिलेगी। उन्होंने इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री तथा केन्द्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का आभार व्यक्त किया है।

धर्मशाला में तिब्बती व विदेशी पर्यटकों के पंजीकरण कार्यालय का शुभारम्भ

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने 2.41 करोड़ रुपये की लागत से धर्मशाला के पुलिस अधीक्षक परिसर में तिब्बती व विदेशी पर्यटकों के पंजीकरण कार्यालय का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने पुलिस लाईन धर्मशाला में 2.75 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित प्रशासनिक कार्यालय खण्ड का भी लोकार्पण किया।

खाद्य, नागरिक अपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर, शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी, विधायक होशियार सिंह, पूर्व सांसद कृपाल परमार, उपायुक्त सन्दीप कुमार, भाजपा के संगठन सचिव पवन राणा, पलिस महा निदेशक एस.आर मरड़ी, आईजी अतुल फुलजले व अन्य इस अवसर पर उपस्थित थे।

शिमला में होगा गौ सेवा आयोग का मुख्यालय

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग के अध्यक्ष पशु पालन मंत्री होंगे यह जानकारी प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने दी। अतिरिक्त मुख्य सचिव (पशु पालन), अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व), अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन), प्रधान सचिव (आबकारी व कराधान), सचिव (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज), सचिव (भाषा एवं संस्कृति), डीन डॉ.जी.सी नेगी पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर, कांगड़ा, पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश को सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है जबकि निदेशक पशुपालन हिमाचल प्रदेश इसके सदस्य सचिव होंगे।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष जिला सोलन के अशोक कुमार होंगे। इस आयोग में 10 अन्य गैर सरकारी सदस्य होंगे जिसमें जिला बिलासपुर के अश्वनी कुमार डोगरा, जिला मण्डी के चेत राम तथा स्वामी अभिषेक गिरी, जिला ऊना के सुशील कुमार तथा कृष्णपाल शर्मा, जिला सिरमौर के जगदीप, जिला शिमला के सुशांत देष्टा, जिला कांगड़ा के अशोक कुमार शर्मा, जिला हमीरपुर के आशीष कुमार तथा जिला कुल्लू के शेर सिंह है।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश गौ सेवाआयोग में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में जिला चम्बा के संदीप कुमार, जिला सोलन के देव राज चौधरी, देवानंद गौतम तथा दिनेश कुमार शास्त्री, जिला शिमला के राम कृषि भारद्वाज, राजेन्द्र राणा तथा रोशन लाल, जिला ऊना के सुराम सिंह, जिला कांगड़ा के चन्द्रशेखर तथा जिला हमीरपुर के डॉ.अशोक को मनोनीत किया गया है।

इस आयोग के उपाध्यक्ष तथा गैर सरकारी सदस्यो की सेवाएं नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष तक की अवधि के लिए मान्य होगी।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग का मुख्यालय शिमला में होगा।

2019 लोकसभा आम चुनावों के लिये राज्य स्तरीय प्रमाणीकरण समिति का गठन

शिमला/शैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश देवेश कुमार ने बताया कि 2019 के लोकसभा के आम चुनावों के दृष्टिगत एक राज्य स्तरीय प्रमाणीकरण समिति का गठन किया गया है जो राजनीतिक दलों व संगठनों से टीवी चैनलों/केबल नेटवर्क/रेडियो/वीडियो/सोशल मीडिया वेबसाईटों पर विज्ञापनों के प्रमाणीकरण से निपटने के लिए प्राप्त आवेदनों का निपटारा करेगी।

उन्होंने कहा कि इस समिति का गठन अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त सचिव (चुनाव), हिमाचल प्रदेश शिमला की अध्यक्षता में किया गया है, जिसमें निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) शिमला संसदीय क्षेत्र, केन्द्र निदेशक आकाशवाणी शिमला, केन्द्र निदेशक दूरदर्शन केन्द्र शिमला, संयुक्त निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश तथा सहायक निदेशक (समाचार) आकाशवाणी शिमला इस समिति के सदस्य होंगे।

उन्होंने बताया कि यह समिति टीवी चैनलों/केबल नेटवर्क/रेडियो/ वीडियो/सोशल मीडिया वेबसाईटों के विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के लिए सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों जिनका मुख्यालय हिमाचल प्रदेश राज्य में है और सभी संगठनों, जिनका पंजीकृत कार्यालय हिमाचल प्रदेश में है का निपटारा करेगी।

हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान के मुख्य सचिवों के बीच पौंग बांध विस्थापितों के मुद्दों पर द्वि-पक्षीय बैठक

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल तथा राजस्थान के मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता के मध्य पौंग बांध विस्थापितों से सम्बन्धित मुददों के निदान के लिए एक द्वि-पक्षीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार पौंग बांध विस्थापितों के मुददों पर विस्तार से चर्चा की गई।

हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव ने बैठक में बताया कि यदि राजस्थान पौंग बांध विस्थापितों को भूमि प्रदान नहीं करती है, तो हिमाचल प्रदेश में ही विस्थापितों के लिए भूमि चयनित कर खरीदे और जिसकी भरपाई राजस्थान सरकार को करनी होगी। इस पर राजस्थान के मुख्य सचिव ने कहा कि वे इस मामले के बारे में राज्य सरकार को अवगत करवाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति में इतनी बड़ी धनराशि देने में असमर्थ है तथा सरकार का औपचारिक निर्णय हिमाचल सरकार को बता दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार शेष बचे सभी पौंग बांध विस्थापितों को राजस्थान में ही भूमि उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने प्रदेश सरकार को आश्वासन दिया कि राजस्थान के पास लम्बित पाए लगभग 2000 से अधिक मामलों को शीघ्र भूमि के प्लॉट उपलब्ध करवा दिए जाएंगे।

राजस्थान के मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान सरकार ने 800 भूमि के पट्टे विस्थापितों के लिए तैयार कर दिए हैं, जिन्हें दो चरणों में पौंग बांध विस्थापितों को प्रदान किया जाएगा। सर्व सहमति से यह तय हुआ कि 28 फरवरी तथा 11 मार्च, 2019 यह भू पट्टे विस्थापितों को प्रदान कर दिए जाएंगे।

बैठक में मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल ने बताया कि विस्थापितों को शीघ्र भू पट्टे प्रदान करने के लिए प्रयास किए जाएंगे जिसके तहत हिमाचल प्रदेश सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा एक कॉमन पोर्टल बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक चैक लिस्ट भी तैयार की जाएगी, जिससे राजस्थान के सक्षम वरिष्ठ अधिकारी द्वारा विस्थापितों को भू पट्टा देने से पूर्व सत्यापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी भू पट्टों की जियो मैपिंग करवाई जाएगी।

मनरेगा के तहत वर्ष 2019–20 के लिए 850 करोड़ रुपये स्वीकृत

शिमला/शैल। ग्रामीण विकास सचिव डॉ. आर.एन. बत्ता नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में ग्रामीण विकास को लेकर आयोजित बैठक में शामिल हुए। बैठक में वर्ष 2019-20 की वार्षिक कार्य योजना की समीक्षा की गई।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के तहत 800 करोड़ रुपये व्यय किए गए है जो सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त मनरेगा के तहत 100 करोड़ रुपये जारी किए गए है, जो 31 मार्च, 2019 तक उपयोग में लाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत वर्ष 2019-20 के लिए 850 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं यदि आवश्यकता हुई तो और धनराशि उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2019-20 के लिए 7800 आवास स्वीकृत किए गए हैं।

डॉ. बत्ता ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों के विपणन व उत्पाद विकास के लिए परामर्श सेवा उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया।

जिस शत्रु से आप दुश्मन के साथ धोखा करने से धन का नाश होता है और ब्राह्मण के साथ धोखा करने से कुल का नाश होता है..."चाणक्य"

जटिल होती जा रही है कश्मीर की समस्या, पुलवामा हमले को हल्के में न ले सरकार

गौतम चौधरी

पुलवामा हमले के दिन मैं देहरादून में था। किसी पत्रकार मित्र को जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम के बारे में पूछा तो उसी ने पुलवामा हमले के बारे में बताया। इत्तफाक से उसी दिन शाम को वसंत विहार में एक सांस्कृतिक संगठन की बैठक के दौरान एक रिटायर अधिकारी से मुलाकात हो गयी। उक्त अधिकारी के नाम और दायित्व की चर्चा करना यहां ठीक नहीं होगा लेकिन उन्होंने जो बातें बताई वह बेहद महत्वपूर्ण है। उस अधिकारी के साथ चर्चा के बाद मेरे सोचने का ढंग बदल गया। उन्होंने वही बात बताई जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे हैं। मसलन सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके नेतृत्व वाली सरकार से पांच सवाल पूछे हैं। सुरजेवाला का पहला सवाल है कि आप अपनी खुफिया तंत्र की विफलता के लिए जिम्मेदारी क्यों नहीं स्वीकार करते? दूसरा सवाल, स्थानीय आतंकियों को भारी मात्रा में आरडीएक्स, कार्बाइन और रॉकेट लांचर आए कहां से प्राप्त हुए? तीसरा सवाल, प्रधानमंत्री मोदी के दावे के अनुसार, नोटबंदी से आतंकवाद पर लगाम क्यों नहीं लगा? चौथा सवाल, पुलवामा हमले के 48 घंटे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस की रिपोर्ट और आतंकियों के वीडियो को नजर अंदाज क्यों कर दिया गया? पांचवा सवाल, हवाई मार्ग से जवानों को क्यों नहीं ले जाया गया, सीआरपीएफ के आवेदन को क्यों ठुकराया गया?

उक्त अधिकारी ने एक-दो और सवाल जोड़े। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के बारे में जानकारी एकत्रित करना और उसे हर वक्त अपने रडार में रखना हर गुप्तचर संस्था की जिम्मेवारी होती है लेकिन यहां हमारी इंटेलिजेंस चूक गयी। उन्होंने एक और इन बात बताई। उन्होंने कहा कि पहले तो यह कहा गया कि पुलवामा विस्फोट में 350 किलोग्राम आरडीएक्स उपयोग किया गया है। फिर बाद में उसे घटाकर 80 किलोग्राम बताया गया और अब 60 किलोग्राम बताया जा रहा है। इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए इससे गुप्तचर संस्थाओं के प्रति जनता के विश्वास में कमी आती है और जनता हताश हो जाती है, जिससे सीमा पर लड़ने वाले जवानों का मनोबल कमजोर होता है। इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक लड़ाई में हमें बेहद सतर्क रहना होता है, जिसकी कमी देखने को मिल रही है। उन्होंने यह भी बताया कि जितने किलोग्राम आरडीएक्स के बारे में बताया जा रहा है वह एक-दो दिनों में जुटाया नहीं जा सकता है। इसके लिए लम्बे समय की जरूरत पड़ी होगी लेकिन हमारे इंटेलिजेंस के पास इसकी सूचना नहीं पहुंची यह बेहद खतरनाक है।

पंजाब के एक रिटायर गुप्तचर सेवा के अधिकारी से जब बात हुई, तो उन्होंने बताया कि राजीव गांधी की हत्या में बहुत कम आरडीएक्स का उपयोग हुआ था। पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह को मारने के लिए आतंकवादियों ने 20 किलोग्राम आरडीएक्स का उपयोग किया था। उन्होंने बताया कि पुलवामा हमले में जितने आरडीएक्स के उपयोग की बात बताई जा रही है वह सत्य से परे है। यदि उतने आरडीएक्स का प्रयोग हुआ होता तो क्षति बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी।

फिर इस हमले के बाद जो सत्ता पक्ष और विपक्ष का रवैया रहा है वह बेहद छिछला रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमले के बाद फैरी खाना-पूर्ति के अलावा कश्मीर में कुछ खास देखने-सुनने को नहीं मिल रहा है। सरकार की स्थिति तो यह है कि पहले छः अलगाववादी नेता की सुरक्षा छीनी गयी लेकिन उन नेताओं में सैयद अली शाह गिलानी का नाम शामिल नहीं था। जब गिलानी के नाम पर सरकार की आलोचना होने लगी तो सरकार ने उसकी सुरक्षा भी वापस ले ली। इस प्रकार के निर्णय से जाहिर होता है कि सरकार के अंदरखाने में भी अंतरविरोध चल रहा है। इसके बाद जवानों की एयर लिफ्टिंग के निर्णय में सरकार को एक हफ्ते का समय लग गया।

इस हमले की समीक्षा के दौरान मुझे लगा कि इसके लिए कई चूक जिम्मेदार हैं। पहली बात तो युद्ध भूमि में घोड़े नहीं बदले जाते हैं। सरकार ने कई स्तर पर घोड़े बदले, यानी कश्मीर पर अपनी नीति में बदलाव किया। इसके कारण कश्मीर का ऑपरेशन कमजोर हुआ। इसमें महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर भाजपा का प्रदेश में सरकार बनाना और बीच में ही उसके साथ गठबंधन तोड़ लेना भी शामिल है। यही नहीं सरकार ने बीच में ही वहां के राज्यपाल को भी बिना किसी कारण के बदल दिया। कई अधिकारियों को इधर से उधर किया गया। इसके कारण हमारे गुप्तचर यूनिट को आपस में कॉर्डिनेशन बिठाने में स्वभाविक रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा।

इसके बाद, हमले की जो हमारी मीडिया ने रिपोर्टिंग की है वह भी बेहद सतही समझा जाना चाहिए। हमने पाकिस्तान की बात को लक्ष्य कर अपनी प्रोपगैंडा नीति बना ली। पहले पाकिस्तान की मीडिया ने यह कहा कि फिदायीन आतंकवादी जम्मू-कश्मीर का ही है। हमने बिना किसी खोज-खबर के मान लिया कि आतंकवादी हमारे कश्मीर का ही है। मान लिया कि वह हमारे कश्मीर का ही है लेकिन उसका प्रशिक्षण तो पाकिस्तान में ही हुआ होगा। हमें इस बात को जोर-शोर से प्रचार करना चाहिए था लेकिन हम उस प्रचार में विफल रहे। हमारी मीडिया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के प्रेस- फूटेज को दिखा-दिखा कर यह साबित करने में लगी रही कि पाकिस्तान बेहद डर गया है लेकिन उसका भारत को कोई लाभ तो नहीं मिला। हमारी मीडिया को ज्यादा से ज्यादा जैश-ए-मोम्मद की कारगुजारियों के बारे में बताना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसका असर हमारी विदेश नीति पर लम्बे समय तक पड़ने वाला है।

इस तमाम बिन्दुओं को देखकर ऐसा लगता है कि चाहे हम पड़ोसियों पर कितना भी आरोप मढ लें लेकिन पुलवामा हमला हमारी चूक का प्रतिफल है। दुश्मन देश, चिहित हैं। वे भारत के साथ दोस्ती जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। लम्बे समय से वे हमारे खिलाफ छद्म युद्ध चला रहे हैं। ऐसे में हम युद्धभूमि में हैं, यह हमें नहीं भूलना चाहिए। हम यदि छोटी-सी भी भूल करते हैं तो उसका परिणाम बेहद खतरनाक होने वाला है, हमें ऐसा समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो व्यवस्था बनाई गयी है और वह हमारे हित में है तो उसके साथ छेड़-छाड़ उचित नहीं है। तीसरी बात यह है कि हमारा प्रचार तंत्र हमारी नीतियों को परिलक्षित करने वाला होना चाहिए, जो इस हमले में दिखा नहीं। कुल मिलाकर देखें तो सरकारी स्तर पर भी इस हमले को हल्के में लिया जा रहा है। खासकर सत्तापक्ष के लोगों के द्वारा जिस प्रकार की सतही भाषा का उपयोग हो रहा है उससे यही लगता है कि इस अति गंभीर मामले को सत्ता पक्ष के लोग हल्के में ले रहे हैं। इसे हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। हम पाकिस्तान पर हमला करें या न करें लेकिन चूक से सबक जरूर लेना चाहिए।

सम्पादकीय

क्या पुलवामा का विकल्प युद्ध ही है

पुलवामा आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री ने देश को विश्वास दिलाया है कि शहीदों के खून का बदला लिया जायेगा। इसी के साथ यह भी स्पष्ट किया है कि सेना को इस संद्धर्भ में फैसला लेने का पूरा अधिकार दे दिया है। इस हमले का जवाब कब कहां और कैसे दिया जायेगा यह सब सेना तय करेगी। प्रधानमन्त्री के इस आश्वासन के बाद देशभर में उभरी प्रतिक्रियाओं में भी यही सामने आया है कि देश की जनता भी इसमें कोई निर्णायक कदम चाहती है। देश की यह प्रतिक्रिया स्वभाविक है क्योंकि इन्हीं घटनाओं में हमारे सैंकड़ों सैनिक शहीद हो चुके हैं इन सैंकड़ों घरों के चिराग बुझे हैं। हर घटना के बाद ऐसी ही प्रतिक्रियाएं और ऐसे ही दावे सामने आते रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राईक तक की गई। नोट बन्दी तक का देश ने स्वागत किया क्योंकि इससे आतंकवाद खत्म हो जायेगा यह कहा गया था। लेकिन आज पुलवामा ने इन सारे दावों पर नये सिरे से प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया है। हर घटना के बाद पाकिस्तान को गाली देकर जनता के आक्रोश को शांत किया जाता रहा है। हर बार हर आतंकी घटना के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की बात की जाती रही है और पाकिस्तान हर बार इन आरोपों के ठोस सबूत मांगता रहा है। आज भी यही हो रहा है। यह सबूत हम मित्र देशों के साथ सांझा करने को तैयार हैं लेकिन पाकिस्तान को देने के लिये तैयार नही है। यह कैसी कूटनीति है? क्या हम मित्र देशों को दिये जाने वाले सबूत पाकिस्तान को भी साथ ही देकर अर्न्तराष्ट्रीय समुदाय में अपना पक्ष और पुख्ता नही कर सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री यही कह रहे हैं कि सबूत दो तो हम करवाई करेंगे और उन्होने जमात-उद-दावा तथा फलह-ए-इन्सानियत फाऊंडेशन के खिलाफ कारवाई शुरू कर दी है। इन संगठनों के पाकिस्तान में 300 से ज्यादा मदरसे स्कलू, अस्पताल, एम्बुलैन्स सेवा-प्रकाशन संस्थान और 50,000 स्वयं सेवक कहे जाते हैं। यदि सही में पाकिस्तान ने इन संगठनों के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाये हैं तो अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में उसकी बात भी सुनी जायेगी। ऐसे में क्या यह सही नही होगा कि भारत सरकार पाकिस्तान के इन दावों की पड़ताल करके इसका सच देश और दुनिया के सामने रखे। क्योंकि युद्ध एक भयानक विकल्प है। न्यूर्याक के तीन विश्वविद्यालयों के एक अध्ययन की जो रिपोर्ट न्यूर्याक टाईम्स के माध्यम से सामने आयी है उसमें एक ही दिन में करोड़ो लोगों के मरने की आशंका जताई गयी है। रिपोर्ट के मुताबिक यदि युद्ध होता है तो उसके परिणाम सदियों तक भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है और पाकिस्तानी सेना पर जिस ढंग से वहां के आतंकी संगठनों को सहयोग करने के आरोप लगते आये हैं उससे यह खतरा और बढ़ जाता है। युद्ध में जाने से पहले इसे भी ध्यान में रखना आवश्यक होगा।

क्योंकि यह एक स्थापित सत्य है कि आतंकी को मार देने से ही आतंकी का खात्मा नही हो जाता है। मार देने से केवल अपराधी गैंग समाप्त किये जा सकते हैं। यदि आतंक विचार जनित है तो उसके लिये समानान्तर विचार लाया जाना आवश्यक हैं जम्मूकश्मीर में यह सामने आ चुका है कि सेना की कारवाई का विरोध वहां के छात्रों/युवाओं ने पत्थरबाजी से दिया। हजारों पत्थरबाजों को जेल में डाला गया और फिर छोड़ना पड़ा। पत्थबाजी की इस मानसिकता को समझना होगा। आज केन्द्र सरकार ने वहां के अठारह नेताओं की सुरक्षा वापिस ले ली है। इन नेताओं पर आरोप है कि यह लोग अलगाववादी गतिविधियों को समर्थन देते हैं। इन्हें विदेशों से आर्थिक मदद मिलती है। यदि यह आरोप सही हैं तो फिर सरकार पर ही यह सवाल आता है कि फिर इन लोगों को यह सुरक्षा दी ही क्यों गयी थी? क्योंकि विदेशों से गैर कानूनी तरीके से आर्थिक मदद लेना एक बहुत बड़ा अपराध है और फिर उस मदद से अलगाववाद को बढ़ावा देना तो अपराध को और बड़ा कर देता है। क्या सरकार इन लोगों को सुरक्षा देकर स्वयं ही अपरोक्ष में इन गतिविधियों को बढ़ावा नही दे रही थी? पुलवामा के बाद सारे देश मे जहां कही भी कश्मीरी छात्र पढ़ रहे थे उन्हें प्रताड़ित किये जाने की घटनाएं समाने आयी है और सर्वोच्च न्यायालय को इन्हें सुरक्षा दिये जाने के आदेश करने पड़े हैं। क्या इस तरह की घटनाओं से जम्मू कश्मीर का आम नागरिक विचलित नही होगा। वह क्या सोचगा? वहां के हर नागरिक को तो आतंकी करार नही दिया जा सकता फिर जिन नेताओं की सुरक्षा वापिस ली गयी है उनके खिलाफ सरकार के पास क्या पुख्ता प्रमाण है? इन्हे अभी तक देश के सामने नही रखा गया है। आज सबसे पहले देश को विश्वास में लेने की आवश्यकता है क्योंकि यह पुलवामा में उस समय घटा है जब देश लोकसभा चुनावों में जा रहा है। पुलवामा में हुई सुरक्षा की चुक को लेकर सरकार पर सवाल उठने शुरू हो गये हैं। जब गुप्तचर ऐजैन्सीयों ने सरकार को पहले ही आगाह कर दिया था तो फिर उस चेतावनी को किसके स्तर पर और क्यों नजरअन्दाज किया गया? यह सही है कि देश अब कोई निर्णायक हल चाहता है। युद्ध को ही विकल्प माना जा रहा है। लेकिन युद्ध के परिणाम क्या होंगे उससे कितना विनाश होगा इसका अनुमान भावनाओं में बहकर नही लगाया जा सकता। युद्ध की अपरिहार्यता के ठोस कारण देश के सामने रखने होंगे और इसके पीछे किसी भी तरह की कोई राजनीतिक मंशा नही रहनी चाहिये। क्योंकि देश चुनावों में जा रहा है और सरकार का हर कदम चुनावी चर्चा का विषय बनेगा यह तय है।

"शैल" साप्ताहिक के स्वामित्व एवं अन्य विषयों से सम्बन्धित विवरण

1. प्रकाशन स्थान	:	शैल कार्यालय ऋचा पिंर्टज एण्ड पब्लिशर्ज लक्कड़ बाजार शिमला
2. प्रकाशन अवधि	:	साप्ताहिक
3. मुद्रक का नाम	:	बलदेव शर्मा
4. राष्ट्रीयता	:	भारतीय
5. प्रकाशक का नाम	:	बलदेव शर्मा
6. पता	:	ऋचा पिंर्टज एण्ड पब्लिशर्ज रिवोली बस स्टैण्ड लक्कड़ बाजार शिमला
7. सम्पादक का नाम	:	बलदेव शर्मा
8. उन व्यक्तियों के नाम और पते जो समाचार पत्र के स्वामी और भागीदार या कुल पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक सांझेदार/हिस्सेदार हों	:	कोई नहीं

मैं बलदेव शर्मा घोषणा करता हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

(बलदेव शर्मा)

क्या बेरोजगार युवाओं की फौज ही राजनीति की ताकत है?

'पुण्य प्रसून बाजपेयी'

2019 के चुनाव का मुद्दा क्या है। बीजेपी ने पारंपरिक मुद्दो को दरकिनार रव विकास का राग ही क्यों अपना लिया। कांग्रेस का कारपोरेट प्रेम अब किसान प्रेम में क्यो तब्दील हो गया। संघ स्वदेशी छोड मोदी के कारपोरेट प्रेम के साथ क्यो जुड गया। विदेशी निवेश तो दूर चीन के साथ भी जिस तरह मोदी सत्ता का प्रेम जागा है वह क्यो संघ परिवार को परेशान नही कर रहा है।

जाहिर है हर सवाल 2019 के चुनाव प्रचार में किसी ना किसी तरीके से उभरेगा ही । लेकिन इन तमाम मुद्दो के बीच असल सवाल युवा भारत का है जो बतौर वोटर तो मान्यता दी जा रही है लेकिन बिना रोजगार उसकी त्रासदी राजनीति का हिस्सा बन नहीं पा रही है और राजनीति की त्रासदी ये है कि बेरोजगार युवाओ के सामने सिवाय राजनीति दल के साथ जुडने या नेताओ के पीछे खडे होने के अलावा कोई चारा बच नही पा रहा है। यानी युवा एकजुट ना हो या फिर युवा सियासी पेंच को ही जिन्दगी मान लें, ऐसे हालात बनाये जा रहे हैं। मसलन आलम ये है कि देश में 35 करोड युवा वोटर। 10 करोड़ बेरोजगार युवा। छह करोड़ रजिस्ट्रट बेरोजगार। और इन आंकोड़ो के अक्स में ये सवाल उठ सकता है कि ये आंकडे देश की सियासत को हिलाने के लिये काफी है। जेपी से लेकर वीपी और अन्न आंदोलन में भागेदारी तो युवा की ही रही। लेकिन अब राजनीति के तौर तरीके बदल गये है तो युवाओ के ये आंकडे राजनीति करने वालो को लुभाते है कि जो इनकी भावनाओ को अपने साथ जोड लें, 2019 के चुनाव में उसका बेडा पार हो जायेगा। इसीलिये संसद में आखरी सत्र में प्रधानमंत्री मोदी रोजगार देने के अपने आंकडे रखते है। सडक चौराहे पर रैलियो में राहुल गांधी बेरोजगारी का मुद्दा जोर शोर से उठाते हैं और प्रधानमंत्री को बेरोजगारी के कटघरे में खडा करते हैं। और राजनीति का ये शोर ये बताने के लिये काफी है कि 2019 के चुनाव के केन्द्र में बेरोजगारी सबसे बडा मुद्दा रहेगा। क्योंकि युवा भारत की तस्वीर बेरोजगार युवाओ में बदल चुकी है। जो वोटर है लेकिन बेरोजगार है। जो डिग्रीधारी है लेकिन बेरोजगार है। जो हायर एजुकेशन लिये हुये है लेकिन बेरोजगार है। इसीलिये चपरासी के पद तक के लिये हाथों में डिग्री थामे कितनी बडी तादाद में रोजगार की लाइन में देश का युवा लग जाता है ये इससे भी समझा जा सकता है कि राज्य दर राज्य रोजगार कितने कम है। मसलन आंकोडो को पढ़े और कल्पना कीजिये राज्यस्थान में 2017 में ग्रूप डी के लिये 35 पद के लिये आवेदन निकलते है और 60 हजार लोग आवेदन कर देते है। छत्तिसगढ में 2016 में ग्रूप डी की 245 वेकेंसी निकलती है और दो लाख 30 हजार आवेदन आ जाते है । मध्यप्रदेश में 2016 में ही ग्रूप डी के 125 वेकेंसी निकलती हैं और 1 लाख 90 हजार आवेदन आ जाते है। पं बंगाल में 2017 में ग्रूप डी की 6 हजार वेकेंसी निकलती है और 25 लाख आवेदन आ जाते है। राजस्थान में साल भर पहले चपरासी के लिये 18 वेकेंसी निकलती है और 12 हजार 453 आवेदन आ जाते हैं। मुबंई में महिला पुलिस के लिये 1137 वेकेंसी निकलती है और 9 लाख आवेदन आ जाते हैं। तो रेलवे ने तो इतिहास ही रच दिया जब ग्रूप डी के लिये 90 हजार वेकेंसी निकाली जाती है तो तीन दिन के भीतर ही ऑन लाइन 2 करोड 80 लाख आवेदन अप्लाई होते है । यानी रेलवे में ड्राइवर, गैगमैन, टैक मैन, स्विच मैन, कैबिन मैन, हेल्पर और पोर्टर समेत देश के अलग अलग राज्यो में चपरासी या डी ग्रूप में नौकरी के लिये जो आवेदन कर रहे थे या कर रहे हैं वह कैसे डिग्रीधारी हैं इसे देखकर शर्म से नजरे भी झुक जायें कि बेरोजगारी बडी है या एजुकेशन का कोई महत्व ही देश में नहीं बच पा रहा है। क्योंकि इस फेरहिस्त में 7767 इंजिनियर। 3985 एमबीए। 6980 पीएचडी। 991 बीबीए। करीब पांच हजार एमए। और 198 एलएलबी की डिर्गी ले चुके युवा भी शामिल थे। यानी बेरोजगारी इस कदर व्यापक रुप ले रही है कि आने वाले दिनों में रोजगार के लिये कोई व्यापक नीति सत्ता ने बनायी नहीं तो फिर हालात कितने बिगड़ जायेगें ये कहना बेहद मुश्किल होगा। पर देश की मुश्किल यही नहीं ठहरती। दरअसल नीतियां ना हो तो जो रोजगार है वह भी खत्म हो जायेगा और मोदी की सत्ता के दौर की त्रासदी यही रही कि अतिरक्त रोजगार तो दूर झटके में जो रोजगार पहले से चल रहे थे उसमें भी कमी गई। केन्द्रीय लोकसेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और रेलवे भर्ती बोर्ड में जितनी नौकरिया थी वह बरस दर बरस घटती गई। मनमोहन सिंह के दौर में सवा लाख बहाली हुई। तो 2014 – 15 में उसमें 11 हजार 908 की कमी आ गई। इसी तरह 2015 – 16 में 1717 बहाली कम हुई और 2016 – 17 में तो 10 हजार 874 नौकरिया कम निकली। पर बेरोजगारी का दर्द सिर्फ यही नहीं ठहरता। झटका तो केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम में नौकरी करने वालो की तादाद में कमी आने से भी लगा। मोदी के सत्ता में आते ही 2013 – 14 के मुकाबले 2014 – 15 में 40 हजार नौकरिया कम हो गई। और 2015 – 16 में 66 हजार नौकरिया और खत्म हो गई। यानी पहले दो बरस में ही एक लाख से ज्यादा नौकरिया केन्द्रीय सार्वजिक उपक्रम में खत्म हो गई। हालाकि 2016 – 17 में हालत संबालने की कोशिश हुई लेकिन सिर्फ 2 हजार ही नई बहाली हुई। पर नौकरियों को लेकर देश को असल झटका तो नोटबंदी से लगा। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के जरीये जो भी सोचा वह सब नोटबंदी के बाद काफूर हो गया। हालात इतने बूरे हो गये कि बरस भर में करीब दो करोड़ रोजगार देश में खत्म हो गये। सरकार के ही आंकडो बताते है कि दिसंबर 2017 में देश में 40 करोड 97 लाख लोग के पास काम था। और बरस भर बाद यानी दिसंबर 2018 में ये घटकर 39 करोड़ 7 लाख पर आ गया । यानी ये सवाल अनसुलझा सा है कि फिर सरकार ने रोजगार को लेकर कुछ सोचा क्यों नही। या फिर देश में जो आर्थिक नीति अपनायी जा रही है उससे रोजगार अब खत्म ही होंगे या फिर रोजगार कैसे पैदा हो सरकार के पास कोई नीति है ही नही। ऐसे में आखरी सवाल सिर्फ इतना है कि सियासत ने युवा को अगर अपना हथियार बना लिया है तो फिर युवा भी राजनीति को अपना हथियार बना सकने में सक्षम क्यों नहीं है।

वर्तमान सरकार आरपार की लड़ाई के पक्ष में

यह नए भारत की ताकत ही है कि कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को मिलने वाली सुरक्षा और सुविधाओं के छीने जाने पर फारूख अब्दुल्लाह और महबूबा मुफ्ती जैसे घाटी के नेता शांत हैं। और नए भारत की यह ताकत सिर्फ देश में ही नहीं दुनिया में भी दिखाई दी। – 'डॉ नीलम महेंद्र'

यह सेना की बहुत बड़ी सफलता है कि उसने पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड अब्दुल रशीद गाजी को आखिरकार मार गिराया हालांकि इस ऑपरेशन में एक मेजर समेत हमारे चार जाबाज सिपाही वीरगति को प्राप्त हुए। देश इस समय बेहद कठिन दौर से गुजर रहा है क्योंकि हमारे सैनिकों की शहादत का सिलसिला लगातार जारी है। अभी भारत अपने 40 वीर सपूतों को धधकते दिल और नाम आँखों से अंतिम विदाई दे भी नहीं पाया था, सेना अभी अपने इन वीरों के बलिदान को ठीक से नमन भी नहीं कर पाई थी, राष्ट्र अपने भीतर के घुटन भरे आक्रोश से उबर भी नहीं पाया था, कि 18 फरवरी की सुबह फिर हमारे पांच जवानों की शहादत की एक और मनहूस खबर आई।

पुलवामा की इस हृदयविदारक घटना में सबसे अधिक पीड़ादायक बात यह है कि वो 40 सीआरपीएफ के जवान किसी युद्ध के लिए नहीं गए थे। वे तो छुट्टियों के बाद अपनी अपनी डयूटी पर लौट रहे थे। 'जिहाद' की खातिर एक आत्मघाती हमलावर ने सेना के काफिले पर इस फियादीन हमले को अंजाम दिया। हैवानियत की पराकाष्ठा देखिए कि पाक पोषित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद न सिर्फ हमले की जिम्मेदारी लेता है बल्कि उस सुसाइड बॉम्बर का हमले के लिए जाने से पहले का एक वीडियो भी रिलीज करता है। इंसानियत का इससे घिनौना चेहरा क्या हो सकता है। इससे किसे क्या हासिल हुआ कहना मुश्किल है लेकिन इस घटना ने इतना तो साबित कर ही दिया कि बिना स्थानीय मदद के ऐसी किसी वारदात को अंजाम देना संभव नहीं था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस वीभत्सता में कश्मीरियत जम्हूरियत और इंसानियत ने कब का दम तोड़ दिया है। वो घाटी जो जन्नत हुआ करती थी आज केसर से नहीं लहू से लाल है। वो कश्मीर जो अपनी सूफी संस्कृति के लिए जाना जाता था आज आतंक का पर्याय बन चुका है।

घाटी में आतंक का ये सिलसिला जो 1987 से शुरू हुआ था वो अब निर्णायक दौर में है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जवानों के खून की एक एक बूंद और हर आंख से गिरने वाले एक एक आँसू का ऐसा बदला लिया जायेगा कि विश्व इस न्यू इंडिया को महसूस करेगा।

वर्तमान सरकार के प्रयासों से स्पष्ट है कि वो इस बार आरपार की लड़ाई के पक्ष में है और यह सही भी है। क्योंकि देश में हुए आतंकवादी हमले के बाद इस समय जो देश का माहौल बना हुआ है, वो शायद इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। आज देश की हर आंख नम है, हर दिल शहीदों के परिवार के दर्द को समझ रहा है, हर शीश उस माता पिता के आगे नतमस्तक है जिसने अपना जिगर का टुकड़ा भारत माँ के चरणों में समर्पित किया। हर हृदय कृतज्ञ है उस वीरांगना का जिसने अपनी मांग का सिंदूर देश को सौंप दिया और हर भारत वासी ऋणी है उस बालक का जो पिता के कंधों पर बैठने की उम्र में अपने पिता को कंधा दे रहा है।

ये वाकई में एक नया भारत है जिसमें हर दिल में देशभक्ति की ज्वाला धधक रही है। यह एक अघोषित युद्ध का वो दौर है जिसमें हर व्यक्ति देश हित में अपना योगदान देने के लिए बेचैन है। कोई शहीदों के बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले रहा है तो कोई अपनी एक महीने की तनख्वाह दे रहा है। स्थिति यह है कि 'भारत के वीर' में मात्र दो दिन में 6 करोड़ से ज्यादा की राशि जमा हो गई। आज देश की मन:स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश का बच्चा बच्चा और महिलाएं तक कह रही हैं कि हमें सीमा पर जाने दो हम पाकिस्तान से बदला लेने को बेताब हैं। पूरा देश अब पाकिस्तान से बातचीत नहीं बदला चाहता है। हालात यह है कि पाक से बातचीत करने जैसा ब्यान देने पर सिद्धू को एक टीवी शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है तो कहीं पाकिस्तान से हमदर्दी जताने वाले को नौकरी से बाहर कर दिया जाता है। जिस देश में कुछ समय पहले तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर देश विरोधी नारे लगाने वालों के पक्ष में कई राजनैतिक दलों के नेता और मानववादी संगठन इकट्ठा हो जाते थे, आज वो देश भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारों से गूंज रहा है। टीवी चैनल और सोशल मीडिया देश भक्ति और वीररस की कविताओं से ओतप्रोत हैं। यह नए भारत की गूंज ही है कि अपने भाषणों में हरदम आग उगलने वाले ओवैसी जैसे नेता पहली बार आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं। यह नए भारत की ताकत ही है कि कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को मिलने वाली सुरक्षा और सुविधाओं के छीने जाने पर फारूख अब्दुल्लाह और महबूबा मुफ्ती जैसे घाटी के नेता शांत हैं। और नए भारत की यह ताकत सिर्फ देश में ही नहीं दुनिया में भी दिखाई दी जब आतंकवाद की इस घटना पर विश्व के 48 देशों ने भारत को समर्थन दिया। अमेरिका से लेकर रूस ने कहा कि भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है और वे भारत के साथ हैं।

और यह नए भारत की शक्ति ही है कि आज पाकिस्तान बैकफुट पर है। आज वो अपने परमाणु हथियार सम्पन्न होने के दम पर युद्ध की धमकी नहीं दे रहा बल्कि इस हमले में अपना हाथ न होने की सफाई दे रहा है। यह नए भारत का दम है कि यह हरकत उस पर उल्टी पड़ गई। दरअसल अमरीका की ट्रम्प सरकार द्वारा अफगानिस्तान से अपनी फौज वापस बुलाने के फैसले से आतंकी संगठनों और पाक दोनों के हौसले फिर से बुलंद होने लगे थे। इस समय को उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाने के मौके के रूप में देखा। क्योंकि सेना की मुस्तैदी और ऑपरेशन ऑल आउट के चलते वे काफी समय से देश या घाटी में कोई वारदात नहीं कर पा रहे थे जिससे उन्हें अपने अस्तित्व पर ही खतरा दिखने लगा था और वो जबरदस्त दबाव में थे। उन्होंने सोचा था कि भारत में चुनाव से पहले 'कुछ बड़ा' करके वो भारत पर दबाव बनाने में कामयाब हो जाएंगे जबकि हुआ उल्टा। क्योंकि आज आर्थिक रूप से जर्जर पाकिस्तान सामाजिक रूप से भी पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। और रही सही कसर भारत के प्रधानमंत्री के बदला लेने के संकल्प के बाद 14 तारिख से लगातार भारत के हर गली कूचे में गूंजने वाले पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों ने उसको मनोवैज्ञानिक पराजय दे कर पूरी कर दी। वो पाक अपनी नापाक हरकतों से विश्व में आर्थिक सामाजिक कूटनीतिक और राजनैतिक मोर्चे पर आज बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है। अपने दुश्मन की इस आधी पराजय को अपनी सम्पूर्ण विजय में बदलने का इससे श्रेष्ठ समय हो नहीं सकता जब देश के हर बच्चे में सैनिक, हर युवा में एक योद्धा और हर नारी में दुर्गा का रूप उतर आया हो।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में किया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम–किसान) का शुभारम्भ

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला के सभागार में आयोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले राज्य के लगभग 8,42,600 किसानों को इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 6000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।

उन्होंने कहा कि दिसम्बर, 2018 और जनवरी व फरवरी, 2019 के महीने के लिए 2000 रुपये की पहली किस्त प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं आज तक दर्ज राज्य के 1,41,677 किसानों के खातों में जमा की जाएगी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पंजीकृत होते ही शेष किसानों को भी यह राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह कदम किसानों के कल्याण के प्रति केन्द्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य लघु एवं सीमान्त किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना है तथा यह योजना किसानों को 6,000 रुपये की नकद सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले लघु एवं सीमांत किसानों को

उनके खातों में तीन किश्तों में 2,000 रुपये की प्रत्येक किश्त के रूप में प्रदान की जाएगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि इस योजना के तहत 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की सहायता तीन समान किश्तों में लघु एवं सीमांत किसानों के परिवारों को प्रदान की जाएगी। जिनके पास दो हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि है। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को लाभ हस्तांतरित करने के लिए योजना 1 दिसम्बर, 2018 से प्रभावी होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से देश के 12.5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाली चार महीने की अवधि के लिए पहली किश्त वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में ही पात्र लाभार्थियों को हस्तांतरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गृहिणी सुविधा योजना के तहत लाभार्थी को एक और मुफ्त गैस रिफिल उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई हिमकेयर योजना में 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित किया जा रहा है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार भी प्रदेश में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित कर रही है और इसके लिए बजट में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रयास न केवल किसानों के लिए ज्यादा आय सुनिश्चित करेगा बल्कि जनता को स्वस्थ भोजन भी प्रदान करेगा।

पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद शांता कुमार ने कहा कि यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक क्रांतिकारी योजना है, जो किसानों को उनकी कृषि आय में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 70 वर्षों में किसी ने भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसा दूरदर्शी कदम नही उठाया है। उन्होंने प्रदेश में इस योजना के शुभारम्भ के लिए कांगड़ा जिले को चुनने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि विशेष रूप से भारी वर्षा, ओलावृष्टि, आग आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को नुकसान के समय यह योजना गरीब किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए कांटेदार तार की बाड़ लगाने पर 50 प्रतिशत उपदान देने की भी घोषणा की है।

कृषि मंत्री डॉ. राम लाल मारकण्डा ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा यह योजना पूरे देश में एक साथ आरम्भ की गई है। उन्होंने इस योजना की मुख्य विशेषताओं की भी विस्तृत जानकारी दी।

निदेशक कृषि देसराज शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार, विधायक प्रकाश राणा, कुलपति चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर डॉ.अशोक, उपायुक्त संदीप कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

सराज विधानसभा क्षेत्र के 1200 कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में शामिल

शिमला/शैल। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सारोआ तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाड़ा में विज्ञान खण्ड के निर्माण के लिए 50-50 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी तथा इन स्कूलों में अगले शैक्षिणिक सत्र से विज्ञान कक्षाएं आरंभ कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यह घोषणा मण्डी जिला के सिराज विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरोआ में आयोजित कार्यक्रम 'अखण्ड शिक्षा ज्योति-मेरे स्कूल से निकले मोती' की अध्यक्षता करते हुए की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अखण्ड शिक्षा ज्योति-मेरे स्कूल से निकले मोती कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के पूराने विद्यार्थियों को सम्मानित करना है। इससे न केवल इन पूराने विद्यार्थियों का समाज के लिए दिए गए योगदान के बारे में अवगत करना है, बल्कि इससे स्कूल के विद्यार्थियों को जीवन में सफलता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और अधिक कठोर परिश्रम के लिए प्रेरित करना भी है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि देश हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों में सुरक्षित है और आज भारत उनके सक्षम व दृढ़ नेतृत्व में विश्व गुरू बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग केन्द्रीय नेतृत्व द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ लिए जाने वाले प्रत्येक निर्णय के साथ खड़े है। उन्होंने कहा कि हिमाचल न केवल देव भूमि है बल्कि यह वीर भूमि भी है और प्रदेश के लोगों की सशस्त्र बलों में सेवारत सैनिकों और पूर्व सैनिकों की अधिकतम संख्या है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल उपलब्धियों भरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई नीतियों व कार्यक्रमों से समाज का प्रत्येक वर्ग व प्रदेश का प्रत्येक क्षेत्र लाभान्वित हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ किए गए कार्यक्रम जनमंच से लोगों की समस्याओं और शिकायतों का उनके घर-द्वार के निकट निवारण सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार कार्यभार संभालने के प्रथम दिन से ही गरीब व जरूरतमंदों के कल्याण का लक्ष्य रखकर कार्य कर रही है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने अगले वित्त वर्ष के बजट में निर्णय लिया है कि सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने वाले कर्मचारी के आश्रित को करुणामूलक आधार पर रोज़गार प्रदान करने का निर्णय लिया जबकि पूर्व सरकार द्वारा 50 वर्ष की आयु से पहले मृतक कर्मचारी के आश्रितों को ही करुणामूलक आधार पर रोज़गार दिया जाता था। उन्होंने कहा कि आगामी वित्त वर्ष के लिए अनेक विकासात्मक योजनाओं की भी घोषणा की गई है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करने के लिए हिम केयर योजना भी आरंभ की गई है। उन्होंने तांदी, शिमलीधार तथा कशाहड़ में स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने की घोषणा की। उन्होंने राजकीय प्राथमिक पाठशाला सारोआ में दो कमरों के निर्माण तथा परीक्षा हॉल के निर्माण के लिए 10 लाख रुपये की घोषणा की। उन्होंने बाड़ा में पशु अस्पताल खोलने की घोषणा की। उन्होंने सारोआ में हेलीपैड निर्माण के लिए 10 लाख रुपये की भी घोषणा की। उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न सम्पर्क मार्गो के निर्माण के लिए 65 लाख रुपये की भी घोषणा की।

इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने 65 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले सारोआ-लटोगली उठाऊ पेयजल योजना की आधारशीला रखी।

मुख्यमंत्री ने प्राथमिक पाठशाला सराजी को माध्यमिक पाठशाला तथा माध्यमिक पाठशाला जोहट को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बाड़ा के भवन निर्माण की घोषणा की। उन्होंने इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के लिए अपनी ऐच्छिक निधि से 31000 रुपये प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कुकलहा के लिए एक नए पटवार वृत को खोलने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 'अखण्ड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती' के तहत स्कूल के पूर्व छात्रों को सम्मानित किया।

उन्होंने प्रदेश सरकार तथा हंस ट्रस्ट की ओर से सिराज के विभिन्न महिला मण्डलों को ढोलक, चिमटा, दरी, व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, छड़ी (वॉकिंग स्टिक्स) व अन्य उपकरण प्रदान किए। उन्होंने हंस फाउंडेशन के परविन्दर विष्ट का निस्वार्थ भावना से किए जा रहे कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज कार्यक्रम के दौरान विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक महिला मण्डल को 20,000 रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।

स्कूल की प्रधानाचार्य बिंटी देवी ने मुख्यमंत्री तथा अन्य उपस्थित गणमान्यों का स्वागत किया। उन्होंने विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रधानाचार्य, विद्यार्थी एवं कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 31000 रुपये का चैक प्रदान किया।

उन्होंने इस अवसर पर केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी।

सराज विधानसभा क्षेत्र के 1200 कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने भाजपा में शामिल हुए कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए आश्वासन दिया कि उन्हें पार्टी में उचित सम्मान व स्थान दिया जाएगा। पार्टी में हर एक कार्यकर्ता एक समान है और सभी की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सुदृढ़ देश बनाने में एक समान जिम्मेदारी है। सराज भाजपा मण्डल के अध्यक्ष शेर लसह ने मुख्यमंत्री और अन्य उपस्थित गणमान्यों का इस अवसर पर स्वागत किया।

विश्व बैंक और कोरियन टीम ने हिमाचल प्रदेश में ठोस कचरा प्रबन्धन पर की बातचीत

शिमला/शैल। विश्व बैंक की टीम वरिष्ठ पर्यावरण विशेषज्ञ पियुष डोगरा, ए.एस. हरिनाथ व सलाहकार डॉ. संपत और कोरिया ग्रीन ग्रोथ ट्रस्ट फंड की टीम जिसका नेतृत्व डॉ.ली. डौंग हून चेयरमेन कोरिया स्टूडेंट अल्पाइन फेडरेशन यूनिवर्सिटी सियोल कोरिया, पार्क मिन-सन, जीयून, डिप्टी मैनेजर आईसीएलसीआई गीता संदल ने हिमाचल प्रदेश में ठोस कचरा प्रबन्धन पर तकनीकी सहायता के लिए प्रदेश का दौरा किया और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की।

पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों के साथ टीम ने 19 फरवरी, 2019 को नगर निगम शिमला, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, एनएसी अर्की का दौरा किया और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट पर स्थानीय मुद्दों की पहचान की।

बाद में टीम ने मुख्य सचिव बी. के. अग्रवाल को ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए ठोस कचरे के लिए प्रभावी प्रबंधन रणनीति में राज्य की सहायता के लिए मुख्य बिंदुओं के बारे में जानकारी दी।

टीम ने डेस्ट के विशेषज्ञों के साथ आधे दिन की चर्चा की और टीम ने अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हिमाचल सरकार की अध्यक्षता में एक शिखर सम्मेलन में सभी हितधारक विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए राज्य सरकार द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, वित्तीय संसाधनों आदि के बारे विस्तार से चर्चा की।

इस अवसर पर आरडी धीमान ने कहा कि कोरिया और विश्व बैंक के विशेषज्ञ हिमाचल प्रदेश में ठोस अपशिष्ट समस्या और चुनौतियों के लिए व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और अन्य हितधारक विभागों के साथ मिलकर काम करेंगे।

आरडी धीमान ने कहा कि बैठक के दौरान आपसी सहयोग के क्षेत्रों की पहचान की गई है। जिसमें हिमाचल प्रदेश में जलवायु क्षेत्र आधारित नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन रणनीति विकसित करना शामिल है। साथ ही सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तातरण, अनुकुलित म डल के लिए प्रशिक्षण और नियम पुस्तिका के विकास, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट पर क्षमता निर्माण और छोटी एवं सूक्ष्म म डल आधारित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता शामिल है।

पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक डीसी राणा ने बैठक के दौरान कहा कि कोरिया और विश्व बैंक की यह टीम दक्षिण एशिया में तीन देशों पाकिस्तान, नेपाल और भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का तकनीकी विश्लेषण करेगी और हिमाचल सरकार के साथ काम करेगी।

उन्होंने कहा कि यह विश्लेषण अगले 9 महीनों में पूरा हो जाएगा और उसके बाद ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन और इसके लिए नीधि जुटाने के लिए अलग-अलग गतिविधियों को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीम कल बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण (बीबीएनडीए) और उसके बाद धर्मशाला का दौरा करेगी।

सदस्य सचिव हि.प्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड डॉ.आर.के. पूर्थी, कोरियाई प्रतिनिधियों प्रोफेसर डॉ. ली डौंग हून और चांग क्वो चो ने इस अवसर पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन पर प्रस्तुतियां दी।

प्रधान मुख्य अरण्यपाल अनिल कपिल, निदेशक ग्रामीण विकास राकेश कंवर, निदेशक शहरी विकास राम कुमार गौतम, अतिरिक्त निदेशक पर्यावरण परवीण गुप्ता और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री तथा मुख्यमंत्री ने देहरा में रखी केन्द्रीय विश्वविद्यालय की आधारशिला

शिमला/शैल। केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावेड़कर तथा मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कांगड़ा जिला के देहरा में हिमाचल प्रदेश के केन्द्रीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। प्रकाश जावेड़कर ने इस अवसर पर कहा कि इस विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए वन स्वीकृत उस समय दी गई थी जब वह केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री थे। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय से क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित होने के अतिरिक्त क्षेत्र के युवाओं को गुणात्मक उच्च शिक्षा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय परिसर का कार्य शीघ्र पुरा करना सुनिश्चित बनाने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध करवाएगी।

केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने प्रदेश के लिए अनेक राष्ट्रीय संस्थान स्वीकृत किए है। उन्होंने कहा कि ऊना के लिए आई.आई.आई.टी तथा मण्डी के लिए आई.आई.आई.टी स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि मण्डी जिला के लिए कलस्टर विश्वविद्यालय भी स्वीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त प्रदेश के लिए अनेक केन्द्रीय विद्यालय भी स्वीकृत किए गए है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार देश के लगभग 9 लाख स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से डिजिटल बोर्ड उपलब्ध करवाने के लिए बचनबद्ध है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय के दो विभिन्न स्थानों पर दो परिसर होंगे। उन्होंने कहा कि पहला परिसर धर्मशाला के निकट जदरंगल जो 750 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला होगा। दूसरा परिसर देहरा में 287 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद वन स्वीकृति के लिए कैंप अधिनियम के तहत 6

करोड़ रुपये की राशि जमा की ताकि वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों के लिए बदलकर शीघ्र परिसर का निर्माण आरंभ किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों परिसरों के निर्माण पर 1300 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी और इनका निर्माण कार्य अगले तीन वर्षों में पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परिसर का लगभग 1 हजार हेक्टेयर तक विस्तार होगा जो कि क्षेत्र का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय होगा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए बचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान शिक्षा क्षेत्र पर 7044 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे है जबकि अगले वित्त के लिए 7600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो राज्य सरकार का हिमाचल प्रदेश को देश भर में शिक्षा हब बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र अन्य राज्यों से आगे है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की साक्षरता दर केरल के बाद दूसरे स्थान पर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार द्वारा शिक्षा के बारे में बड़े-बड़े दावे किए जाते रहे है परंतु धरातल पर कुछ नही हुआ। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम एक माह के दौरान बिना किसी बजट प्रावधान के चुनाव में फायदे के दृष्टिगत 21 महाविद्यालयों खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने राज्यों के सभी शिक्षण संस्थानों में आवश्यक अधोसंरचना व स्टॉफ सुनिश्चित बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ किए गए विकासात्मक व कल्याणकारी नीतियों व कार्यक्रमों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने प्रदेश के लिए 10,500 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाएं स्वीकृत की है।

मुख्यमंत्री राजकीय माध्यमिक पाठशाला खाबली को उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा उच्च पाठशाला बणे-दी-हट्टी को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। इस वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बणे-दी-हट्टी का नाम शहीद विजेन्द्र सिंह रखने की भी घोषणा की। उन्होंने हरिपुर के लिए लोक निर्माण विभाग के लिए उपमण्डल की भी घोषणा की और देहरा के 100 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल को 150 बिस्तरों वाले अस्पताल में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की। उन्होंने हरिपुर कॉलेज में विज्ञान कक्षाएं आरंभ करने तथा डलयारा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने उप तहसील हरिपुर को तहसील में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 52 करोड़ रुपये की ब्रिकस परियोजनाएं भी देहरा क्षेत्र के लिए स्वीकृत की जाएगी। उन्होंने कहा कि नगर परिषद देहरा के नए भवन का भी निर्माण किया जाएगा।

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश में पूर्व भाजपा सरकार के दौरान प्रदेश में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी परंतु राज्य की पूर्व कांग्रेस सरकार ने इस दिशा में कुछ भी नही किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में अग्रणी राज्य के रूप में आंका गया है जो राज्य सरकार के प्रदेश के युवाओं को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की वचनबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 3500 से अधिक अध्यापकों को नियुक्त किया गया है और 5 हजार से अधिक अध्यापकों को भर्ती करने की प्रक्रिया जारी है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।

हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय केन्द्र सरकार का हिमाचल प्रदेश और विशेषकर कांगड़ा के लोगों के लिए विशेष उपहार है। उन्होंने कहा कि 2015 में ही केन्द्र द्वारा सभी स्वीकृतियां प्रदान कर दी गई थी परंतु उस समय की प्रदेश सरकार केन्द्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध करवाने में असफल रही। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।

स्थानीय विधायक होशियार सिंह ने केन्द्रीय मंत्री तथा मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा क्षेत्र की विभिन्न विकासात्मक मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा।

पूर्व मंत्री रविन्द्र सिंह रवि ने कहा कि पूर्व प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय विश्व विद्यालय स्थापित करने में अनेक अड़चने पैदा की और वर्तमान प्रदेश सरकार के प्रयासो के कारण ही आज इस परिसर का शिलान्यास हो सका है।

केन्द्रीय विश्व विद्यालय के कुलपति डॉ. कुलदीप चंद अग्निहोत्री ने केन्द्रीय मंत्री व मुख्यमंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रदेश के युवाओं को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होगा।

पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल, कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर, उद्योग मंत्री ब्रिकम सिंह, राज्य भाजपा के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला, हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री, केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के संयुक्त सचिव जी.सी होसूर, प्रधान सचिव शिक्षा के. के पंत, केन्द्रीय विश्व विद्यालय हिमाचल प्रदेश के कुलाधिपति हरमिन्द्र सिंह बेदी, निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. अमरजीत शर्मा, उपायुक्त कांगड़ा संदीप कुमार, पुलिस अधीक्षक संतोष पटयाल व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने क्लस्टर विश्वविद्यालय तथा आईटीआई भवन की रखी आधारशिला

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मण्डी जिला के द्रंग क्षेत्र के नारला में विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि छात्राओं को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य के द्रंग में अटल आदर्श विद्यालय खोला जाएगा और द्रंग की नमक की खानों की खुदाई का मामला केन्द्र सरकार से उठाया जाएगा।

इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने 10.72 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले वल्लभ क्लस्टर विश्वविद्यालय भवन, 10.86 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन तथा 14.82 करोड़ रुपये की लागत से सी.आर.एफ के तहत निर्मित होने वाले ऊहल नदी पर कमांद में निर्मित होने वाले 130 मीटर लम्बे पुल की आधारशिला रखी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान प्रदेश का समग्र एवं संतुलित विकास सुनिश्चित हुआ है। प्रदेश सरकार आम आदमी के कल्याण को लक्ष्य रखकर कार्य कर रही है। वर्तमान सरकार ने अपनी पहली मंत्रिमण्डल की बैठक में बिना किसी आय सीमा के सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आयु को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया है, जिससे लाखों लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स योजना जिसका उन्होंने आज शिलान्यास किया है से क्षेत्र की पानी की समस्या का समाधान सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जटींगरी, पराशर तथा बरोट क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध करवाएगी ताकि पर्यटकों को इस घाटी के मनोरम व अनछूए पर्यटक स्थलों के भ्रमण का अवसर प्राप्त हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आश्वस्त किया है कि हिमाचल प्रदेश को विकास के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मण्डी शिवरात्री मेले को अंतरराष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया गया है तथा इस बारे अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मण्डी शहर को पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने की योजना है, इसके लिए शहर में शिव धाम विकसित किया जाएगा जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में उनके द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए प्रस्तुत बजट में समाज के लगभग प्रत्येक वर्ग के लिए अनेक योजनाओं की घोषणा की गई है। बजट घोषणा में शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए वित्तीय लाभ की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सुनिश्चित बनाया है कि प्रदेश का प्रत्येक घर धुआंमुक्त हो इसके लिए सरकार द्वारा आगामी दो-तीन माह में शेष बचे परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने ऐसे परिवारों जिनके परिवार का कोई सदस्य गंभीर बीमारी के पीड़ित है को प्रतिमाह 2 हजार वित्तीय सहायता प्रदान करने की भी घोषणा की है।

जय राम ठाकुर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरोट को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने, पधार में उप-अग्निशमन केन्द्र खोलने, माध्यमिक पाठशाला भमसूई तथा गरलोग को उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा प्राथमिक पाठशाला कुनू, कोशाल तथा सिदबुधाणी को माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्न करने की घोषणा की। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुधार में विज्ञान खण्ड तथा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सलाह के लिए स्कूल भवन की भी घोषणा की। उन्होंने क्षेत्र के आठ सम्पर्क मार्गो के निमार्ण व स्तरोन्यन के लिए 61 लाख रुपये की घोषणा की।

इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 7.6 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले भियूली तूंग सड़क राज्य-2 तथा 5.90 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली अरनैहर बूंगा सड़क का भूमि पूजन किया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना के अंतर्गत 58.5 लाख रुपये की लागत से अरनैहर बंगा सड़क की शकरयार खड्ड पर 19.75 मीटर लम्बे आरसीसी टी-बीम पुल की भी आधारशिला रखी। उन्होंने 1.42 करोड़ रुपये की लागत से ग्राम कुफरी की ढंढवाल खड्ड से ढूंढा क्षेत्र की बस्तियों के लिए पेयजल आपूर्ति योजना का भी शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने ब्रिक्स के अंतर्गत 60.58 करोड़ रुपये की लागत से बड़ागांव, कुफरी, धर्मछयान, टिक्कर इत्यादि बस्तियों के लिए उठाऊ जलापूर्ति योजना की आधारशिला रखी। उन्होंने ब्यास नदी से पधार तहसील के पाली, सिलाग, कुन्नू गांव के लिए उठाऊ सिंचाई योजना की भी आधारशिला रखी। उन्होंने ग्राम पंचायत बठैहरी के जुलग संगलवाह उठाऊ जलापूर्ति योजना के संवर्द्धन व स्तरोन्यन की भी आधारशिला रखी। इन योजनाओं पर क्रमशः11.93 तथा 2.78 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 'बेटी है अनमोल योजना' के अंतर्गत कन्या शिशु के माता-पिता को 10-10 हजार रुपये के ड्राफ्ट तथा किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी दिए। उन्होंने 'विधायक निधि योजना' के अंतर्गत क्षेत्र के महिला मण्डलों को 20-20 हजार रुपये प्रदान किए।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महिन्द्र सिंह ठाकुर, अध्यक्ष हिमफैड निहाल चंद शर्मा, अध्यक्ष वक्फ बोर्ड राज बाली, भाजपा के जिला अध्यक्ष रणवीर सिंह, भाजपा के प्रवक्ता अजय राणा भी अन्य सहित इस अवसर पर उपस्थित थे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

वीरभद्र के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोप तय

क्या भाजपा पहले की तरह इस बार भी इसे चुनावी मुद्दा बना पायेगी

शिमला/शैल। पर्व मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह और उनके एलआईसी ऐजैन्ट आनन्द चौहान के खिलाफ अन्ततः दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोप तय कर दिये है। इसी मामले में वीरभद्र सिंह की पत्नी पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह और अन्य नामजद अभियुक्तों के खिलाफ पहले ही आरोप तय हो चुके हैं। अब आरोप तय होने के बाद इस प्रकरण में नियमित कारवाई चलेगी। यदि इस मामले में कहीं वीरभद्र सिंह के खिलाफ कभी कोई फैसला आ जाता है तब इसमें सर्वोच्च न्यायालय तक अपीलों का दौर चलेगा और इस तरह कई दशकों तक मामला अदालतों में चलता रहेगा जैसे पडित सुख राम का चल रहा है। यदि इसमें वीरभद्र के खिलाफ फैसला आ जाता है तब वीरभद्र भी सुखराम के साथ एक ही पायेदान पर आ खड़े होंगे। गौरतलब है कि इसी आय से अधिक संपत्ति मामले को ईडी भी धन शोंधन के तौर पर देख रहा है। बल्कि ईडी में तो वीरभद्र सिंह और प्रतिभा सिंह को छोड़कर अन्य कथित अभियुक्तों आनन्द चौहान और वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर जैसे लोगों की तो जांच के दौरान गिरफ्तारी भी हो चूकी है। ईडी के प्रकरण की भी जांच पूरी होने के बाद इसका चालान भी अदालत में दायर हो चुका है और उसमें अब आरोप तय होने की प्रक्रिया चलेगी। बल्कि धन शोधन मामले में एक समय ईडी वक्कामुल्ला चन्द्र शेखर की जमानत रद्द करने की गुहार तक भी लगा चुका है। इस आग्रह पर अदालत ने सख्ती दिखाते हुए ईडी से यहां तक पूछ लिया था कि वह वक्कामुल्ला को लेकर तो इतनी गंभीरता दिखा रहे हैं लेकिन इसी मामले के मूल अभियुक्त वीरभद्र सिंह को लेकर उसका आचरण भिन्न क्यों रहा है। ईडी जब अदालत की इस टिप्पणी का कोई संतोषजनक जवाब नही दे पाया था तब दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी के आग्रह को सिरे से ही खारिज कर दिया था। लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक हल्कों में ईडी के जमानत रद्द करवाने के आग्रह को राजनीतिक अर्थो में देखा जा रहा है। बल्कि ईडी के इस आग्रह के बाद वीरभद्र और आनन्द चौहान के उन आरोपों को नये सिरे से एक अर्थ मिल जाता है जब उन्होने मामले की सुनवाई कर रहे जज के खिलाफ लिखित में पक्षपात करने के आरोप लगाये थे। इस पूरे परिदृश्य में वीरभद्र सिंह का यह सीबीआई और ईडी का मामला इन लोकसभा चुनावों के दौरान एक बार फिर केन्द्रिय मुद्दा बनने के मुकाम पर पहुंच गया है। स्मरणीय है कि भाजपा ने वीरभद्र के इस मामले को 2014 के लोकसभा चुनावों और फिर 2017 के विधानसभा चुनावों में खूब भुनाया था। यह आरोप लगाये थे कि वीरभद्र के तो पेड़ों पर भी नोट उगते हैं। ऐसे में इन लोकसभा चुनावों में यह प्रकरण किस तरह से उठाया जाता है यह देखना दिलचस्प होगा। सीबीआई में यह मामला लगभग एक दशक तक रहा है। जिस भाजपा ने इसे दो बार चुनावों भुनाया वह अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में वीरभद्र सिंह और प्रतिभा सिंह को एक दिन के लिये भी गिरफ्तार नही कर पाये यह एक कडवा सच है। ईडी अदालत के सवाल का कोई जवाब तक नही दे पाया। जबकि वीरभद्र और आनन्द चौहान के पक्षपात को लेकर अदालत पर लगाये आरोप आज भी यथास्थिति खड़े हैं यही नही अब जब सीबीआई अदालत में इस प्रकरण में आरोप तय होने की स्थिति आयी तब वीरभद्र और प्रतिभा सिंह ने सीबीआई के अधिकार क्षेत्र को ही उच्च न्यायालय में यह कह चुनौती दे दी कि जांच ऐजेन्सी को यह मामला किसी भी सरकार ने नही भेजा है और न ही किसी सरकार से इसमें मुकद्दमा चलाने की अनुमति ली गयी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वीरभद्र के इस आग्रह के बाद चालान को न तो रद्द किया और न ही कारवाई को स्टे किया। लेकिन इस पर सीबीआई से जवाब अवश्य मांग लिया है। अब यदि वीरभद्र का यह तर्क सही पाया जाता है तो एक बार फिर सीबीआई स्वयं आरोपों के घेरे में आ जायेगी। क्योंकि सीबीआई ऐसे अपने ही तौर पर किसी भी मामले की जांच शुरू नही कर सकती है। इसी के साथ जब ऐसे मामलों में चालान दायर किया जाता है तब चालान के साथ ही मुकद्दमा चलाने की अनुमति भी संलगन करनी पड़ती है। वीरभद्र के मुताबिक ऐसा कुछ भी नही है। जांच ऐजेन्सी की जांच के बाद चालान तैयार और दायर हो जाने के बाद भी सरकार ऐसे मामलों को वापिस ले सकती है। सरकार के अनुमति न देने पर ही मामला खत्म हो जाता है। जयराम सरकार ने ही विधानसभा अध्यक्ष डॉ. बिन्दल का मामला तो उस स्टेज पर वापिस लिया है जब कि उसमें अभियोजन पक्ष की गवाहियां तक हो चुकी थी। फिर वीरभद्र के मामले में तो सीबीआई और ईडी दोनों के आचरण को लेकर जांच के दौरान ही आरोप लगते रहे हैं। उच्च न्यायालय तक ईडी के आचरण पर सवाल उठ चुका है। फिर बिन्दल के मामले के सामने वीरभद्र का मामला बहुत छोटा पड़ जाता है।

इस तरह वीरभद्र का मामला एक ऐसे मोड पर पंहुच चुका है कि जहां से भाजपा को भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी कथित प्रतिवद्धता का लाभ उठाने के लिये कोई जगह नही रह जाती है। बल्कि इस बार कांग्रेस के पास भाजपा पर राजनीतिक प्रतिशोध लेने के आरोप लगाने के लिये यही मामला एक बड़ा हथियार बन जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार भ्रष्टाचार किसी भी दल का मुद्दा बन पाता है या नही।

हिमाचल पुलिस ने भी कश्मीरी छात्रों को किया गिरफ्तार

शिमला/शैल। पुलवामा में हुए आंतकी हमले के बाद पूरे देश की पुलिस अलर्ट पर आ गयी है। सभी जगह कश्मीरी छात्रों और अन्य कश्मीरियों पर नजर रखी जा रही है। हिमाचल में भी कई जगहों पर लोगों ने कश्मीरीयों को काम न देने के प्रस्ताव पारित किये हैं। इसी संर्द्भ में हिमाचल पुलिस ने बद्दी और नौणी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे कुछ कश्मीरी छात्रों को गिरफ्तार किया है।

सोशल साइट फेसबुक पर राष्ट्र की अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली पोस्ट डालने के आरोप में सोलन पुलिस ने डाक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में पढ़ने वाले जम्मू कश्मीर के शेपियां व बांदीपुर के रहने वाले दो छात्रों को सोलन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों को सोमवार शाम को सोलन की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास प्रतिभा नेगी की अदालत मे पेश किया गया व अदालत ने दोनों को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

पुलिस ने इनके मोबाइल को भी अपने कब्जे में ले लिया है। दोनों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 बी और 34 के तहत मामला दर्ज किया है। उधर, विवि प्रशासन ने अपने स्तर पर कारवाई करते है दोनों छात्रों को विवि से निलंबित कर दिया है।

पुलिस के मुताबिक नौणी विवि के प्लांट पेथोलॉजी में एमएससी कर रहे पीरजादा तबरीश फयाज ने फेसबुक पर 2011 से 2013 के बीच बहुत सी राष्ट्र विरोधी टिप्पणियां की है। उसने अपने फेसबुक पर लिखा की कश्मीर में भारतीय सेना का रहना गैरकानूनी है। कश्मीर भारत का अंग नहीं है। यह पाकिस्तान का हिस्सा है। यह टिप्पणियां इसने 2011 से 2013 के दौरान की है। इसके अलावा भी इसने आतंकवादियों की कई पोस्टें शेयर की है। इसके फोन की गैलरी में बुरहान वानी से लेकर कई तस्वीरें मिली है।

पीरजादा एमएससी के दूसरे समेस्टर का छात्र है व शोपियां का रहने वाला है। दूसरा छात्र आकिब रसूल बीएससी कक्षा का पहले समेस्टर का छात्र है और बांदीपुरा का रहने वाला है। इसने अपने फेसबुक प्रोफाइल को 2017 में बदला है। इसने अपने प्रोफाइल पर लिखा है आइसीसी ब्लीड ग्रीन, आई स्पोर्ट पाकिस्तान।

एएसपी सोलन शिव कुमार ने से कहा कि इन दोनों ने ये तमाम चीजें अपने फेसबुक से हटाई नहीं है। बीते रोज इस बावत विवि में हंगामा भी हुआ और छात्रों ने आपत्ति जताई। इस पर विवि प्रशासन ने इन दोनों छात्रों का मामला पुलिस के सुपुर्द कर दिया और बीती रात को इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि मामला स्थानीय अधिवक्ता नीरज भारद्वाज की शिकायत पर दर्ज किया गया है। संभवतः इनके लैपटॉप भी पुलिस ने कब्जे में ले लेगी। इन्हें अदालत में पेश किया जाएगा।

याद रहे इससे पहले पुलिस ने बरोटीवाला थाना के तहत चितकारा विवि के एक छात्र को धारा 153 के तहत गिरफ्तार किया था। उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

डेढ़ लाख किसानों के खाते में दो-दो हजार जमा करवाने की तैयारियों में पटवारियों की छुट्टियां रद्द

शिमला/शैल। दो हैक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना छह हजार रुपए की रकम देने के प्रावधान को लागू करने के लिए प्रदेश की जयराम सरकार ने प्रदेश के तमाम पटवारियों की छुटियां गुपचुप तरीके से रदद कर दी है। कोशिश यह की जा रही है कि आगामी लोकसभा चुनावों से पहले यह रकम पात्र किसानों के खातों में चली जाए इस बावत सरकार ने 22 फरवरी तक तमाम पटवारियों को किसानों के फार्म भर कर देने के फरमान जारी किए है। फार्म के साथ किसान के बैंक खाते व आधार कार्ड की फोटोस्टेट प्रतियां भी लगाई जा रही है। ताकि किसी तरह की मुश्किल न रहे। रकम न भी जाए कम से कम किसानों को आस तो बंधा ही दी गई है कि अगर देश में मोदी सरकार आएगी तो उनके खाते में छह हजार तो निश्चित तौर पर जमा हो जाएगे।

सचिवालय से जुड़े भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक प्रदेश से तीन लाख से ज्यादा किसानों फार्म सरकार के पास पहुंच गए है व इन पर लोकसभा चुनावों से पहले कार्यवाही करने के संभावना है। किसानों को मिलने वाली इस रकम के बाद भाजपा को इसका कितना चुनावी लाभ मिलेगा यह अलग मसला है लेकिन जिस तरह नोटबंदी के दौरान बैंक कर्मचारियों की रात दिन ड्यूटियां लगी थी उसी तरह अबकी बार पटवारियों की ड्यूटियां लगाई गई है।

जयराम सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार की ओर से अंतरिम बजट में इस योजना के घोषित होने के तुरंत बाद मंत्रिमंडल की बैठक में इस बावत फैसला कर लिया था। इसके बाद 12 फरवरी से तमाम पटवारियों की छुटियों का फरमान उन्हें वट्सएप पर ही सुना दिया गया । इस बावत प्रदेश के तमाम पटवारखानों में दो पन्ने का फार्म भी पहुंचा दिया गया। पटवारी ये फार्म किसानों से फोटोस्टेट करवा कर इसमें किसानों की खेती योग्य जमीन का लेखा जोखा भर कर रोजाना जिला उपायुक्तों को रिपोर्ट भेज रहे है और जिला उपायुक्त रोजाना प्रदेश के मुख्य सचिव को रिपोर्ट भेज रहे है। समझा जा रहा है कि ये तेजी केंद्र सरकार के आदेशों पर दिखाई जा रही है। पटवारियों को रोजाना तीन से चार बजे के बीच रिपोर्ट जिला के अपने आला अफसरों को भेजनी होती है।

पटवारियों को रविवार के दिन भी ड्यूटी पर जाने के फरमान है और शाम को आठ आठ बजे तक ड्यूटी ली जा रही है। इसके अलावा बाकी सारे काम छोड़ दिए गए है। पटवारियों के मुताबिक अगर इसके अलावा कोई एक दो काम आ गया तो वह कर देते है, अन्यथा अभी इसी पर जोर है। किसानों कि जमीने अलग अलग गांवों मे होती है तो ऐसे में सारा रिकार्ड छान कर फार्म भरना होता है। कभी दस फार्म ही भरे जाते है तो कभी 40 से पचास तक भी भर लिए जाते है। इस काम के लिए उन्हें वेतन के अलावा अलग से कोई राशि मिलेगी इस बावत उनका कहना है कि कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जयराम सरकार का यह पहला काम है जो इतनी तेजी से हो रहा है।

इस राकेट स्पीड से चल रहे काम से पता नहीं भाजपा को आगामी लोकसभा चुनावों में वोट मिलेंगे या नहीं लेकिन इसी बहाने किसानों का कुछ तो भला हो ही जाएगा।

इस तेजी से अगले 48 घंटों में प्रदेश के 141677 किसानों के खाते में दो हजार रुपए डलने वाले है। प्रदेश में दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले 8,42,600 किसान है। इनमें से तीन लाख 11 हजार 554 के फार्म अपलोड हो चुके है और 141677 किसानों के फार्म वेरीफाइ हो चुके है। इन 141 677 किसानों के खाते में अगले 48 घंटों में दो हजार की रकम जमा हो जाएंगे। यह 28 करोड़ 33 लाख 54 हजार रुपए बन रहे है। निदेशक कृषि देसराज ने कहा कि बाकी किसानों के कागजात वेरीफाई किए जा रहे है। इनके खाते में भी शीघ्र ही दो हजार रुपए जमा हो जाएंगे।

उधर, मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला के सभागार में आयोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि किसानों को इस योजना के तहत सालाना 6000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।

उन्होंने कहा कि दिसम्बर, 2018 और जनवरी व फरवरी, 2019 के महीने के लिए 2000 रुपये की पहली किश्त प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं आज तक दर्ज राज्य के 1,41,677 किसानों के खातों में जमा की जाएगी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पंजीकृत होते ही शेष किसानों को भी यह राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह कदम किसानों के कल्याण के प्रति केन्द्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।